स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–23, अंक–6, ज्येष्ठ–आषाढ़ 2072, जून 2015

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

एक आंकड़े के मुताबिक देश में घातक खाद्य एवं पेय उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों से निपटने में प्रति वर्ष 80 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे रोकने के लिए कानून नहीं है। पर सच्चाई है कि कानून का ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने और उनकी गुणवत्ता को स्तरीय बनाए रखने के लिए . . .

अ नु क्र म

स्वदेशी पत्रिका (कवर पेज) /1
विज्ञापन /2
अनुक्रम /3
पाठकनामा/उन्होंने कहा /4

आवरण कथा :
धीमे जहर के स्वाद से मासूमों को बचाइए
– अरविन्द जयतिलक /6

प्रतिक्रिया : मैगी के बहाने कुछ मूल प्रश्न
– डॉ. वेद प्रताप वैदिक /8

अर्थव्यवस्था : तीव्र विकास के बेबुनियाद दावे
– डॉ. भरतझुनझुनवाला /10

विश्लेषण : मानसून पर निर्भर है देश की अर्थव्यवस्था
– जयंतीलाल भंडारी /12

कृषि : समितियों का सिलसिला की जगह अन्नदाता पर दें ध्यान
– देविन्दर शर्मा /14

दृष्टिकोण : रूक सकती हैं किसान आत्महत्याएं
– डॉ. अश्विनी महाजन /16

रपट /18

स्वदेशी जागरण मंच की गतिविधियाँ /19

विज्ञापन /20–21

स्वदेशी पत्रिका पढ़ें और पढ़ायें /22

समस्या : जहरीले दूध के कारोबार पर लगे रोक
– शशांक द्विवेदी /23

पर्यावरण : मैगी प्रकरण के बहाने पर्यावरणीय प्रश्न
– अरुण तिवारी /25

मुद्दा : आज भी बदलने को तैयार नहीं चीन
– ब्रह्मा चेलानी /28

आतंकवाद : पूर्वोत्तर में आतंक की अनदेखी का अंजाम
– पंकज चतुर्वेदी /30

लोकतंत्र : चुनावी राजनीति से ऊपर सामाजिक बदलाव
– भारत डोगरा /32

समाचार परिक्रमा /34

विज्ञापन /39–40

पाठकनामा

किसान को अपनी भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर रॉयल्टी मिले

राष्ट्राध्यक्ष फोर्ट बिलियम के नेतृत्व में अंग्रेज सरकार सर्वप्रथम 1824 में विभिन्न योजनाओं हेतु जमीन की आवश्यकता पूरी करने के लिए Land Acquisition Bill 1824 का निर्माण बंगाल राज्य के लिए करती है 1839, 1850, 1852, 1870 एंव 1894 में समय समय पर बदलाव करते हुए देश में अपनी सुविधानुसार रोड, नहर एंव रेलवे तथा अन्य योजनाओं हेतु देश की भूमि का जबरन अधिग्रहण करती रही। आजादी के बाद भारत सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल 1894 को ही अपनाया।

आज भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष और कई संगठन विरोध कर रहे हैं। परंतु जब मैंने 2013 एवं 2015 का विश्लेषण किया तो मुझे भी भूमि अधिग्रहण बिल में तीन खामियां मिली हैं :–

LAAR (A) Bill 2015 सेक्सन 2(2): अनुसार औद्योगिक गलियारें के दोने तरफ 1 किमी तक की जमीन अधिग्रहित होगी जो इस जमीन के व्यावसायीकरण की अनंत संभावनाओं की तरफ इशारा करता है। सरकार की पिछले कई वर्षों से दो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लम्बित हैं। (1) दिल्ली मुंबई औद्याोगिक कॉरीडोर, (2) अमृतसर कोलकाता कॉरीडोर, जिसके माध्यम से सरकार लघु एवं मध्यम उद्योगों के सामानों का आयात निर्यात करने का एक प्रारुप प्रस्तावित है।

LAAR (A) Bill 2015 Section 3(j): में कंपनी के स्थान पर निजी संस्था शब्द को शामिल किया गया है जिसके लिए जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रोपाइटरशिप, पार्टनरसिप, कंपनी, कार्पोरेशन एंव नान प्राफिट आर्गनाइजेशन को शामिल किया गया है। नॉन प्राफिट आर्गनाइजेशन के अंतर्गत सोसायटी, ट्रस्ट एंव एनजीओ शामिल होती है। इस बिल के पास होने के बाद एनजीओ जैसी संस्थाएं इसका बडे पैमाने पर दुरुपयोग करेगी। वर्तमान में उनकी भूमिका बडे पैमाने पर संदिग्ध है।

LAAR (A) Bill 2015 Section 87 : किसी भी मामले को ज्यादा जटिल बनाने में उनकी बडी भूमिका होती है। भूमि अधिग्रहण एक गंभीर मामला है **CrPC Sec 197** जटिल प्रक्रिया होने के कारण अधिकारी सीधे तौर पर आरोपित नही हो पाते है। सरकारी अधिकारी की जबावदेही सुनिश्चित होनी ही चाहिए।

– आर.के. मिश्र, करावल नगर, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क :150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क:15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस बात पर मुहर लगा चुका है कि योग न सिर्फ तनाव को कम करता है, बल्कि इसके कई दूरगामी फायदे भी हैं।

– राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी

दुनिया के 175 देशों ने तीन महीने में संयुक्त राष्ट्र में विश्व योग दिवस को मंजूरी दे दी लेकिन हमारे यहां इसका विरोध हो रहा है। इसे मनाने से रोकने के प्रयास हो रहे हैं। तो क्या जिन 175 देशों ने इसे मनाने का फैसला किया, उनका भगवाकरण हो गया?

– स्मृति ईरानी

आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती है। भारत 40 सालों से आतंकवाद से जूझ रहा है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। कोई सिद्धांत नहीं होता। मानवता से शत्रुता ही इसका एकमात्र उद्देश्य है।

– प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी

ग्रो इन इंडिया किसी भी रूप में मेक इन इंडिया से कम महत्वपूर्ण नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि सूखे के मंडराते बादल भारतीयों का ध्यान फिर से कृषि की ओर खीचेंगे।

– देविन्दर शर्मा

आधुनिक वस्तुओं का अनियंत्रित इस्तेमाल भारत को अमेरिका का अंधानुयायी बना रहा है। नतीजा यह है कि देश में भयंकर बीमारियां और अपराध बढ़ रहे हैं। इन प्रवृत्तियों पर सिर्फ कानून काबू नहीं पा सकता। यह नेताओं के भी बूते की बात नहीं है। इसके समाधान के लिए हम सबको आगे आना होगा।

– डॉ. वेद प्रताप वैदिक

देशभर में मिलावटी दूध बेखौफ ढंग से संचालित हो रहे गोरखधंधे से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को ठोस नीति बनानी होगी। गांवों, कस्बों और शहरों में स्थानीय स्तर पर प्रशासन को इसके लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश और कड़े कानूनों का प्रावधान होना चाहिए।

– शशांक द्विवेदी

संपादकीय

लाभ के लिए स्वास्थ्य पर दाँव

दुनिया भर में कम से कम 100 बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी हैं जो खाने पिलाने के व्यवसाय से जुड़ी हैं और उनमें से अधिकतर पर यह आरोप है कि ये अपने लाभ के लिए किसी भी देश के कानून, पर्यावरण और वहां के लोगों के स्वास्थ्य को ठेंगे पर रखकर काम करती हैं। शीर्ष 100 में शामिल पेप्सीको, टायसन फूड्स, नेस्ले, जेबीएस, कोका–कोला और क्राफ्ट फूड पर विभिन्न देशों में हजारों मुकदमें चल रहे हैं। ताजा नेस्ले का विवाद सिर्फ यह नहीं दर्शाता कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां मानकों के प्रति लापरवाही बरतती हैं, बल्कि यह भी सिद्ध करता हैं कि ये जानबूझ कर ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करती हैं जिससे उनके उत्पाद की लत लगे और वे सभी उम्र के उपभोक्ताओं को गुलाम बना सके। दो मिनट के स्लोगन वाली मैगी जिस तरह धीरे–धीरे भारतीयों की सेहत में घुन लगा रही थी और हमारे मानक विभाग विज्ञापन के चकाचौंध और इन कंपनियों के फर्जी दावे से प्रभावित हो रहे थे उससे लगता है कि वैश्वीकरण के दुष्परिणाम को भुगतने के लिए हम ही अभिशप्त हुए हैं। मैगी में अनुमन्य मात्रा से अधिक लेड व मोनो सोडियम ग्लूटोमेट पाए जाने की घटना मामूली नहीं है। इस स्विट्जरलैंड की कंपनी ने जानबूझ कर मानव शरीर के लिए बेहद खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया है इसलिए इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमें चलने चाहिए। भारत का खाद्य व पेय बाजार लगभग ढ़ाई लाख करोड़ का है, जिस पर कब्जा करने की होड़ में हमारे स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। नेस्ले का प्रबंधन अब भी इस बात की दुहाई दे रहा है कि उसकी मैगी पूरी तरह सुरक्षित है बावजूद इसके कि कई राज्यों ने मैंगी के सैंपल की जांच अपने–अपने प्रयोगशालाओं में की और हर जांच में यह पाया गया कि मोनोसोडियम ग्लूटोमेट की मात्रा अधिक है। अन्य कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह नेस्ले का इतिहास भी विवादास्पद रहा है और इस कंपनी ने अपने फायदे के लिए मानवता को हमेशा ताक पर रखा है। नेस्ले इसके पहले भी खतरनाक रसायनों के प्रयोग के लिए जिम्मेदार ठहरायी जा चुकी है। इस कंपनी पर पानी , चॉकलेट व अन्य पेय पदार्थों में मिलावट व गुणवत्ता से खिलवाड़ करने के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। यहां तक कि अमरीका में ही इसने पानी के व्यवसाय में काफी गड़बड़ियां की जिसका वहां भारी विरोध भी हुआ। नेस्ले पर बांग्लादेश और अफ्रीकी महाद्वीप में भी निम्न स्तर के उत्पाद बेचने का आरोप लग चुका है। उल्लेखनीय है कि नेस्ले इस समय खाद्य व पेय पदार्थों का व्यापार करने वाली दुनिया की चार बड़ी कंपनियों में शामिल है। इसका कारोबार लगभग 80 देशों में फैला है, जहां लगभग 500 उत्पादन इकाइयों के जरिए पूरी दुनिया में राज करने का इस कंपनी ने लक्ष्य बना रखा है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए पौष्टिक आहार बनाने का दावा यह कंपनी करती रही है, पर हकीकत में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिससे यह पता चलता है कि इस कंपनी ने गरीब देशों के लचर कानूनों की आड़ लेकर खतरनाक खाद्य व पेय पदार्थों का भी धड़ल्ले से व्यापार किया है। 1970 के दशक में तीसरी दुनिया में बच्चों के लिए पौष्टिक दूध लेकर बाजार में उतरने वाली नेस्ले ने अपनी हर कमी को मजबूत मार्केटिंग व प्रचार तंत्र से ढक दिया। हालांकि तब भी नेस्ले के उत्पादों को लेकर काफी बवाल मचा। 1990 के दशक में नेस्ले प्योर लाइफ के नाम से सस्ता पानी लेकर बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों में उतरी जहां इसने सस्ते के नाम पर सामान्य उपलब्ध पानी को ही बेचकर भारी मुनाफा कमाया। आज भी नेस्ले उसी तरह मुनाफा खोरी के लिए अमानवीय व्यापार व्यवहार में लगी है। पहली बार खाद्य में मिलावट या दूषित पदार्थ के इस्तेमाल पर कोई केन्द्र सरकार इतनी गंभीर हुई है। राष्ट्रव्यापी रोक से न सिर्फ नेस्ले जैसी कंपनी को कड़ा सबक मिलेगा, बल्कि मानकों को पूरा करने का अन्य कंपनियों पर भी दबाव बनेगा। अब जरूरत है कि विदेशी कंपनियों के लिए कठोर मानदंड तैयार किए जाएं जो खाद्य व पेय पदार्थ के व्यवसाय में संलग्न है। अन्यथा कुछ दिनों की सक्रियता के बाद फिर उसी लापरवाही का परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ेगा, जिसका पहले पेप्सी कोक और केडबरी जैसी कंपनियों के मामले में हुआ। पेप्सी और कोक के उत्पाद में भी खतरनाक रसायन होने के सबूत मिले थे। पर इन कंपनियों ने आक्रामक विज्ञापन के जरिए अपनी बादशाहत फिर कायम कर ली है। कारण साफ है कि आज भी हमारे देश में पैक फूड के बारे में कोई कठोर मानदंड नहीं बन सका है। अभी तक मिलावटों और नकली पदार्थों तक ही सीमित है। विभिन्न रसायनों के उपयोग और उनकी मात्रा लिखने की अनिवार्यता नहीं है और रसायनों के कारण पड़ने वाले असर के बारे में पैकेट्स पर कोई जानकारी नहीं होती। हमारा खाद्य नियामक संगठन भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण अभी सात साल ही पुराना है। इस विभाग को अपने कामकाज में और परिपक्वता लाने की आवश्यकता है। क्योंकि इस विवाद पर ही बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित और आयातित खाद्य पदार्थों से सुरक्षित रखने का दायित्व है। हाल ही में यूरोप अमरीका और अफ्रीका से आ रहे फलों और सब्जियों में भी खतरनाक कीटाणु होने की आशंका जताई गई है। इस समय पूरी दुनिया से खाद्य पदार्थ हमारे देश में आ रहे हैं, इसलिए मानकों के साथ–साथ जागरूकता भी बढ़ाने की आवश्यकता है, हालांकि मैगी प्रकरण के बाद भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण ने नेस्ले समेत लगभग दस कंपनियों के उत्पादों की भी देश भर में जांच का फैसला किया है। इन उत्पादों में भी नूडल्स पास्ता और नमकीन शामिल हैं, पर इसके साथ यह भी जरूरी है कि उपभोक्ताओं को भी यह जानकारी दी जाए कि किन उत्पादों में कौन से रसायन डाले जाते हैं और कितनी मात्रा के बाद ये मानव शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होते। भारत का उपभोक्ता बहुत संवेदनशील है। इसलिए कंपनियों और नियामक प्राधिकरणों को भी इस मामले में संवेदनशील होना पड़ेगा।

धीमे जहर के स्वाद से मासूमों को बचाइए

एक आंकड़े के मुताबिक देश में घातक खाद्य एवं पेय उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों से निपटने में प्रति वर्ष 80 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे रोकने के लिए कानून नहीं है। पर सच्चाई है कि कानून का ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने और उनकी गुणवत्ता को स्तरीय बनाए रखने के लिए देश में खाद्य संरक्षा और मानक कानून 2006 लागू है।

■ अरविन्द जयतिलक

जब से फास्ट फूड व्यंजन मैगी में लेड व मोनोसोडियम ग्लूटामैट (एमएसजी) जैसे घातक रसायन पाए जाने की खबरें सुर्खियां बनी हैं, लोग सहम गए हैं। अब लोगों की जुबान पर मैगी के स्वाद के चटकारे कम, उसके सेवन से होने वाले नुकसान की चर्चा अधिक है।

टेलीवीजन पर 'टेस्ट भी हेल्थ भी' और 'दो मिनट में मैगी तैयार' का प्रचार अब लोगों को खटकने लगा है। ऐसे मेगास्टारों पर भी भरोसा नहीं रहा जो मैगी की गुणवत्ता का ढोल पीटते हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मैगी के कई पैकेटों को जब्त कर उसकी गुणवत्ता की जांच राज्य की प्रयोगशाला में की। पाया गया कि मैगी में लेड यानी सीसे की मात्रा तय मानकों से अधिक है। विशेषज्ञों की मानें तो बहुत अधिक मात्रा में लेड के सेवन से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इससे न्यूॅरोलॉजिकल समस्या के अलावा खून के संचार में कमी और किडनी फेल होने की स्थिति बन सकती है। चूंकि बच्चे मैगी नूडल्स का सर्वाधिक सेवन करते हैं, ऐसे में उनके शारीरिक विकास में रुकावट के अलावा पेट संबंधी कई बीमारियां मसलन पेट दर्द, नर्व डैमेज और अन्य संवेदनशील अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह मैगी में पाया गया मोनोसोडियम ग्लूटामैट भी सेहत के लिए खतरनाक है। इस केमिकल का उपयोग फास्ट फूड में फ्लेवर का असर बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल से मुंह, सिर, गर्दन में जलन, स्किन संबंधी बीमारी बढ़ती है और साथ ही धीरे–धीरे शरीर भी कमजोर होता है।

हालांकि निर्माता कंपनी ने सफाई दी है कि मैगी नूडल्स में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है जिससे कि शरीर को नुकसान न पहुंचे। लेकिन कंपनी के अनुरोध पर ही जब कोलकाता स्थित नेशनल लैब में जांच हुई तो सामने आया कि मैगी में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामैट की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। ऐसे में मैगी के गुणवत्तापरक होने के दावे बेमानी हो जाते हैं।

निर्माता कंपनी का दावा है कि मैगी के पैकेट की एक्सपायरी डेट छह महीने की होती है और अगर छह महीने में पैकेट नहीं बिकता तो कंपनी में वापस चला जाता है। लेकिन सचाई इसके उलट है। दुकानों पर मैगी के एक्सपायरी पैकेट पड़े रहते हैं और लोग जानकारी के अभाव में उसका इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है कि जहरीले केमिकल का सच सामने आने के बाद क्या सरकार मैगी नूडल्स का लाइसेंस रद्द करेगी? अभी कहना अभी मुश्किल है। देश में ऐसे ढेरों उत्पाद हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं, फिर भी उनकी बिक्री धड़ल्ले से जारी है।

बच्चे मैगी नूडल्स का सर्वाधिक सेवन करते हैं, ऐसे में उनके शारीरिक विकास में रुकावट के अलावा पेट संबंधी कई बीमारियां मसलन पेट दर्द, नर्व डैमेज और अन्य संवेदनशील अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह मैगी में पाया गया मोनोसोडियम ग्लूटामैट भी सेहत के लिए खतरनाक है। इस केमिकल का उपयोग फास्ट फूड में फ्लेवर का असर बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल से मुंह, सिर, गर्दन में जलन, स्किन संबंधी बीमारी बढ़ती है और साथ ही धीरे–धीरे शरीर भी कमजोर होता है।

गत वर्ष सर्वोच्च अदालत ने निर्णय दिया कि कार्बोनेट शीतल पेय पदार्थों की निगरानी और जांच, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसने यह निर्णय शीतल पेय पदार्थो के विनियमन के लिए एक अलग पैनल गठित करने की मांग से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मसला संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। एक अरसे से शीतल पेय पदार्थों की गुणवत्ता और उनमें मिलावट की खबरें चर्चा में हैं। लेकिन कंपनियां आमजन के स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर अपने उत्पादों को धड़ल्ले से बेच रही हैं।

याद होगा जुलाई 2006 में सीएसई की एक रिपोर्ट में कोका–कोला और पेप्सी के पेयों में कीटनाशकों की अधिक मात्रा होने की बात सामने आई थी। सीएसई द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कोका–कोला और पेप्सी के 11 विभिन्न ब्रांडों में कीटनाशकों की उपस्थिति 2003 में पाए गए कीटनाशकों की मात्रा से भी ज्यादा बताई गई। रिपोर्ट में देश के विभिन्न भागों में खरीदे गए 57 सैंपलों में तीन से पांच कीटनाशकों की मात्रा बीआईएस द्वारा तय मानकों से औसतन 24 गुना अधिक थी। कोका–कोला के कोलकाता संयत्र द्वारा उत्पादित एक पेय में कैंसर कारक लिडैन की मात्रा बीआईएस मानकों की तुलना में तकरीबन 140 गुना अधिक थी। सीएसई की इस रिपोर्ट के बाद पेय कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठ खड़े हुए थे। लेकिन आज भी इनकी बिक्री यथावत जारी है। जबकि इस तय से सभी सुपरिचित हैं कि इसमें शामिल घातक रसायनों से शरीर कई गंभीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है।

एक आंकड़े के मुताबिक देश में घातक खाद्य एवं पेय उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों से निपटने में प्रति वर्ष 80 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे रोकने के लिए कानून नहीं है। पर सच्चाई है कि कानून का ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने और उनकी गुणवत्ता को स्तरीय बनाए रखने के लिए देश में खाद्य संरक्षा और मानक कानून 2006 लागू है। इस कानून के मुताबिक घटिया, मिलावटी, नकली माल की बिक्री और भ्रामक विज्ञापन के मामले में संबंधित प्राधिकारी जुर्माना कर सकता है। इस कानून के तहत अप्राकृतिक व खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर दो लाख रुपए, घटिया खाद्य पदार्थ की बिक्री पर पांच लाख रुपए, गलत ब्रांड खाद्य पदार्थ की बिक्री पर तीन लाख रुपए और भ्रामक विज्ञापन पर 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन सचाई यह है कि तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है और उनका हौसला बुलंद होता है।

जरूरत इस बात की है कि कानून का सख्ती से पालन हो और अन्य देशों की तरह खाद्य संरक्षा के मानक तय करने के साथ निगरानी के लिए एजेंसियों का गठन हो। उदाहरण के लिए अमेरिका की खाद्य संरक्षा व्यवस्था दुनिया के बेहतरीन तंत्रों में शामिल है। इसे स्थानीय, राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया है। यहां का फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फूड कोड प्रकाशित करता है। इसमें खाद्य संरक्षा के मानक तय किए गए हैं जिनका उल्लंघन गैरकानूनी है। इसी तरह आस्ट्रेलिया की आस्ट्रेलियाई फूड अथारिटी उपभोक्ताओं तक शुद्ध खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए खाद्य कारोबार पर खाद्य संरक्षा मानकों को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू कराने का काम करती है। जर्मनी में उपभोक्ता अधिकार और खाद्य संरक्षा विभाग इस मामले को देखता है। पूरे जर्मनी में भोज्य पदार्थ बेचने के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है लेकिन वह कानून के मुताबिक तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन भारत में स्थिति उलट है। खाद्य संरक्षा और मानक कानून हमारे देश में मजाक बनकर रह गया है। उचित होगा कि केंद्र और राज्य जहरीले खाद्य पदार्थों पर रोकथाम लगाए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

मैगी के बहाने कुछ मूल प्रश्न

वर्ष 2006 में सरकार ने खाद्य–सुरक्षा और शुद्धता कानून पास किया था, जिसके अंतर्गत साधारण जुर्माने से मौत की सजा तक का प्रावधान था लेकिन क्या आज तक किसी को भी फांसी पर लटकाया गया? कई राज्य ऐसे हैं, जिनमें खाद्य–पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए जितने इंस्पेक्टरों का प्रावधान है, उसके आधे ही नियुक्त हैं। जो नियुक्त हैं, उनके काम में जरुरी मुस्तैदी नहीं है और जो मुस्तैद हैं, उनमें से ज्यादातर रिश्वत से ठंडे कर दिए जाते हैं।

■ डॉ. वेद प्रताप वैदिक

बहुराष्ट्रीय नेसले कंपनी की मैगी नामक सिंवैया जहरीली है या नहीं, यह अभी पूरी तरह से तय नहीं हो पाया है लेकिन अभी तक जितने भी परीक्षण हुए हैं, उनमें से ज्यादातर में मैगी को खतरनाक पाया गया है। उसमें दो ऐसे तत्व पाए गए हैं, जो काफी खतरनाक हैं। इसी आधार पर कई राज्यों ने मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है इससे उसका दस हजार करोड़ रुपए का धंधा अधर में लटक गया है।

कुछ प्रयोगशालाओं की राय है कि मैगी में शीशे की मात्रा जितनी होनी चाहिए, उससे वह सात गुना ज्यादा है। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक रसायन भी खतरे के बिंदु से ज्यादा है। अभी तो ये सिर्फ दो ही आपत्तिजनक तत्व पाए गए हैं। गहरी जांच होने पर अन्य खतरनाक तत्व भी पाए जा सकते हैं। खाने की चीजों में शीशे की अधिकता के कारण मनुष्य के शरीर में रक्तचाप, किडनी और स्नायविक तंत्र की समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह मोनोसोडियम ग्लूटामेट के कारण अनेक शारीरिक और मानसिक गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ये इतने धीरे–धीरे होती हैं कि लंबे समय तक इनका पता ही नहीं चलता।

सिर्फ मैगी ही नहीं, ये जहरीले रसायन पीजा, बर्गर, चिकन, पेटिस, कोला जैसे अनेक 'जंक फूड' में मिला दिए जाते हैं ताकि वे ज्यादा चटपटे, ज्यादा स्वाद और ज्यादा ताजा लगें। अनेक विशेषज्ञों और डॉक्टरों का कहना है कि ये रसायन 'मौन हत्यारे' हैं। लेकिन नेसले कपनी अभी भी दावा कर रही है कि उसकी वस्तुओं में इन रसायनों की मात्र उतनी ही है, जितनी होनी चाहिए।

मान लें कि नेसले का दावा ठीक है या उसे प्रयोगशालाएं बाद में ठीक करार दें तो भी क्या मैगी सिंवैया जैसी बनी–बनाई चीजों का सेवन हम भारतीयों के लिए ठीक है? इस मूल प्रश्न का हम उत्तर खोजें, इसके पहले हमें यह पूछना चाहिए कि मैगी, जैसे खाद्य–पदार्थों का यह मामला क्या मिलावट का मामला नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुनाफा लूटने के खातिर सिर्फ विदेशी कंपनियों ही मिलावट करती हैं। भारत–जैसे देशों में वे विशेष छूट लेती हैं और लापरवाही भी करती हैं लेकिन हमारे देसी विक्रेता भी किसी से कम नहीं हैं। उन्हें पकड़ने और दंडित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? त्यौहारों के दिनों में मिठाइयों में अखाद्य पदार्थों की मिलावट के हादसे हर शहर और गांव में सुने जाते हैं। दूध और मावे में कितनी जहरीली चीजों को मिलाया जाता है, इसकी कल्पना भी साधारण आदमी नहीं कर सकता। और तो और शराब को भी लोग नहीं छोड़ते। शराब अपने आप में विनाशकारी पेय है। उसमें भी ऐसी जहरीली चीजें मिलाई जाती हैं कि हर साल सैकड़ों गरीब लोग मौत की गोद में सोने को मजबूर हो जाते हैं।

सिर्फ मैगी ही नहीं, ये जहरीले रसायन पीजा, बर्गर, चिकन, पेटिस, कोला जैसे अनेक 'जंक फूड' में मिला दिए जाते हैं ताकि वे ज्यादा चटपटे, ज्यादा स्वाद और ज्यादा ताजा लगें। अनेक विशेषज्ञों और डॉक्टरों का कहना है कि ये रसायन 'मौन हत्यारे' हैं। लेकिन नेसले कंपनी अभी भी दावा कर रही है कि उसकी वस्तुओं में इन रसायनों की मात्र उतनी ही है, जितनी होनी चाहिए।

वर्ष 2006 में सरकार ने खाद्य–सुरक्षा और शुद्धता कानून पास किया था, जिसके अंतर्गत साधारण जुर्माने से मौत की सजा तक का प्रावधान था लेकिन क्या आज तक किसी को भी फांसी पर लटकाया गया? कई राज्य ऐसे हैं, जिनमें खाद्य–पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए जितने इंस्पेक्टरों का प्रावधान है, उसके आधे ही नियुक्त हैं। जो नियुक्त हैं, उनके काम में जरुरी मुस्तैदी नहीं है और

जो मुस्तैद हैं, उनमें से ज्यादातर रिश्वत से ठंडे कर दिए जाते हैं।

संसद में प्रस्तुत एक रपट के मुताबिक पिछले साल खाद्य–अशुद्धता के 10,200 मामले पकड़े गए थे, जिनमें से सिर्फ 913 को सजा मिली याने 10 प्रतिशत भी नहीं। नेसले या इस जैसी दर्जनों विदेशी कंपनियां करोड़ों भारतीयों को आज से नहीं, बरसों से ठग रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक औसत भारतीय कैसे मालूम करेगा कि कौनसा पदार्थ शुद्ध है और कौनसा खाने लायक नहीं है? यह काम सरकार का है। अब सरकारें जाग पड़ी हैं तो उसका असर सारे देश में दिखाई पड़ रहा है।

इस तरह के खतरनाक खाद्य–पदार्थों की अंधाधुंध बिक्री के लिए उन फिल्मी सितारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो इनका विज्ञापन करते हैं। वे इनकी बिक्री के लिए तो जिम्मेदार हैं, मिलावट के लिए नहीं। उन्हें क्या पता कि इन पदार्थों में क्या मिलाया जाता है? उन्हें तो अपने पैसों से मतलब है। जो पैसा देगा, वे उसकी डुगडुगी बजाएंगे। इसीलिए वे लोकप्रिय तो होते हैं लेकिन लोक–प्रतिष्ठित नहीं होते। फिर भी हमारे सितारे काफी सजग हैं। उन्होंने पहले भी कुछ विवादास्पद वस्तुओं के विज्ञापन से खुद को अलग कर लिया था।

ऐसे मामलों में सरकार और सितारों की जिम्मेदारी तो है ही लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की है। जनता इन चीजों का आंख मींचकर इस्तेमाल क्यों करती है? यदि वह इन बहिष्कार करने लगे तो ये मुनाफाखोर कंपनियां भारत से भाग खड़ी होंगी।

क्या आपको पता है कि चीन, जापान और इंडोनेशिया के बाद भारत ही मैगी

नेसले या इस जैसी दर्जनों विदेशी कंपनियां करोड़ों भारतीयों को आज से नहीं, बरसों से ठग रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक औसत भारतीय कैसे मालूम करेगा कि कौनसा पदार्थ शुद्ध है और कौनसा खाने लायक नहीं है? यह काम सरकार का है। अब सरकारें जाग पड़ी हैं तो उसका असर सारे देश में दिखाई पड़ रहा है।

की सूखी सिंवैया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? हमारे देश के मध्यम वर्ग का और खासकर उसके जवानों का यह सबसे प्रिय भोजन है। क्यों बन गया है, यह उसका प्रिय भोजन? इसलिए नहीं कि इससे स्वादिष्ट चीजें भारत में नहीं बनतीं। बनती हैं और उनकी संख्या असंख्य है लेकिन कुछ विदेशी चीजें ऐसी हैं, जो बिना किसी कारण महान दिखने लगती हैं। उसका कोई कारण है तो वह हमारी गुलाम मानसिकता या हीनता–ग्रंथि है।

यह *सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है। इसे मैं 'पंचभकार' की व्याधि कहता हूं। यानि हम अपनी भाषा, भूषा, भोजन, भेषज और भजन – इन पांचों मामलों में नकलची बनते जा रहे हैं। लोग अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? कोट–पेंट क्यों पहनते हैं? मांस–अंडा क्यों खाते हैं? एलोपेथी की दवाइयां क्यों लेते हैं और पश्चिम का ऊटपटांग संगीत क्यों सुनते हैं? क्योंकि यदि वे यह सब नहीं करेंगे तो लोग उन्हें पिछड़ा समझेंगे। ये सब सभ्य होने, भद्रलोक होने, एलीट होने की निशानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं विदेशी वस्तुओं, तकनीकों और विचारों के पूर्ण बहिष्कार का समर्थक हूँ। लेकिन उन्हें स्वीकार करते समय हमें हमेशा सावधान रहना होगा कि वे हमारी जीवन–पद्धति से पूरा मेल खाएं।*

जाहिर है कि सामान्य नागरिकों के पास न तो इतनी फुर्सत होती है और न ही उतनी गहरी समझ कि वे बाहर से थोपी जा रही चीजों में अच्छे–बुरे का भेद कर सकें। वे तो भेड़–चाल चलने लगते हैं। वे चलते ही नहीं हैं, दौड़ते हैं। नकलचीपन की यह अंधी दौड़ भारत के मध्यवर्ग की पहचान बन गई है।

इस गुलाम मानसिकता के चलते हम प्राकृतिक जीवन के बदले एक बनावटी जीवन जीने लगे हैं। गर्मी–सर्दी बर्दाश्त करने की बजाय अब मध्यमवर्गीय भारतीय 'एयरकंडीशनर' के बिना सो नहीं सकता। आजकल मकान ऐसे बनने लगे हैं, जिनमें खिड़कियां और झरोखे नहीं होते। हम 'डिब्बाबंद जिंदगी' जीने लगे हैं। खाना भी डिब्बाबंद और मकान भी डिब्बाबंद। हर मध्यमवर्गीय घर में 'फ्रिज' और 'टीवी' आ गया है। फ्रिज का अर्थ है–'बासीघर'। हर चीज को बासी करो। फिर खाओ। यदि फ्रिज में रखी चीज धीरेकृधीरे सड़ती नहीं है तो उसे दोकृतीन महीने रखकर देख लीजिए। टीवी का अर्थ है– अपने घर को नाटकघर बना लो। परिवार की अपनी निजता और पारस्परिकता घटा लो। दूसरे शब्दों में आधुनिक वस्तुओं का अनियंत्रित इस्तेमाल भारत को अमेरिका का अंधानुयायी बना रहा है। नतीजा यह है कि देश में भयंकर बीमारियां और अपराध बढ़ रहे हैं। इन प्रवृत्तियों पर सिर्फ कानून काबू नहीं पा सकता। यह नेताओं के भी बूते की बात नहीं है। इसके समाधान के लिए हम सबको आगे आना होगा। ❑

तीव्र विकास के बेबुनियाद दावे

सरकारी सेवा क्षेत्र में पिछली तिमाही में मात्र 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है जबकि पिछले वर्श इसी तिमाही में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के लिये सरकार ने खर्च करने बन्द कर दिये हैं। इस प्रकार के दूसरे आंकड़े भी उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ रही है। ऐसे में सरकार द्वारा किया जा रहा 7.5 प्रतिशत की विकास दर का दावा संदिग्ध है। याद करें कि अक्टूबर से दिसम्बर 2014 के जीडीपी के आंकड़े पहले 7.5 प्रतिशत वृद्धि के बताये गये थे। बाद में इन्हें 6.6 प्रतिशत पर रिवाइज कर दिया गया था। संभावना है कि पिछली तिमाही के आंकड़ों को इसी प्रकार रिवाइज करके घटा दिया जायेगा।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

भारत सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी से 2015 की तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 7.5 रही है। इसी तिमाही में चीन की विकास दर 7 प्रतिशत रही है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम विश्व की तीव्रतम अर्थव्यवसाी बन गये हैं। परन्तु अभी जश्न मनाने का अवसर नहीं है। चूंकि ये आंकड़े ठोस नहीं दिखते हैं। विषय को समझने के लिये जीडीपी यानि ग्रास डोमेस्टिक प्राडक्ट की तह में जाना होगा।

जीडीपी डाक्टर के पर्चे जैसा दिखता है। कुछ समझ नहीं आता है। वास्तव में बात बहुत आसान है। *जीडीपी हमारी अर्थव्यवस्था की साइज का माप है जैसे किसी की छाती 36'' की होती है तो उसे ''बड़ा'' कहा जाता है।* जीडीपी को किसान के उदाहरण से समझा जा सकता है। किसान कितना बड़ा है इसकी माप उसके खेत में हुए उत्पादन से किया जा सकता है। इसके चार हिस्से होंगे।

पहला हिस्सा – खेत पर काम करने वाले श्रमिकों द्वारा खपत है। जैसे कर्मियों ने गुड़ बनाया और खाया। जितना खाया यह खेत का उत्पादन हुआ।

दूसरा हिस्सा – किसान स्वयं द्वारा की गई खपत का है। जो गुड़ किसान के परिवार ने खाया वह भी उत्पादन में जोड़ा गया।

तीसरा हिस्सा – किसान द्वारा गुड़ की भट्टी बनाने का हुआ। किसान ने ईंट बनाई और भट्टी लगाई। यह भी खेत पर उत्पादन हुआ।

चौथा हिस्सा – किसान द्वारा गेहूं, गन्ने और गुड़ की बिक्री हुयी।

इन चारों को जोड़ लिया जाये तो किसान कितना बड़ा है इसकी माप हो जायेगी। लेकिन जो उत्पादन हुआ उसमें खरीदे गये डीजल, बिजली और फर्टिलाइजर का भी योगदान था। अतः उत्पादन में से खरीदे गये माल का मूल्य घटा दें तो किसान का जीडीपी हमें मालूम पड़ जायेगा।

देश की अर्थव्यवस्था इसी तरह मापी जाती है। पहला हिस्सा देशवासियों द्वारा की गई खपत का होता है। सांख्यकी मंत्रालय द्वारा तमाम परिवारों का सर्वे कराकर अनुमान लगाया जाता है कि एक परिवार ने औसतन कितना आटा, सब्जी, दूध, कपड़ा, टेलिवीजन, टूरिज्म , कम्प्यूटर गेम्स आदि की खपत की। फिर इस रकम को देश के परिवारों की संख्या से गुणा करके देश के समस्त परिवारों की कुल खपत का आकलन किया जाता है। यह खेत श्रमिकों द्वारा की गई खपत के समानान्तर हुआ। दूसरे, सरकार द्वारा की

गई खपत और निवेश का आकलन कर इसे भी ज जीडीपी में जोड़ा जाता है जैसे पुलिस चौकी पर वायरलेस लगाया गया तो देश की जीडीपी बढ़ गया। यह किसान स्वयं द्वारा की गई खपत के समानान्तर हुआ।

तीसरे, देश के उद्यमियों द्वारा कारखानों तथा आफिसों में किये गये निवेश की गणित की जाती है। तमाम कम्पनियों द्वारा उनकी बैलेंस शीट रेजिस्ट्रार आफ कंपनीज़ में दाखिल की जाती है। इनसे अनुमान लगाया जाता है कि देश में कितना उत्पादन निवेश के लिये हुआ। साथ–साथ परिवारों द्वारा मकान आदि में निवेश की मात्रा भी जोड़ी जाती है। यह किसान द्वारा गुड़ की भट्टी में निवेश के समानान्तर हुआ। चौथे, देश द्वारा जितना निर्यात् किया जाता है उसे जीडीपी में जोड़ा जााात है। साफ्टवेयर कम्पनी द्वारा निर्यात् किये गये साफ्टवेयर अथवा कपड़ा उद्योग द्वारा निर्यात किये गये वस्त्रों की गणना करके जीडीपी में जोड़ा जाता है। यह भी देश की अर्थव्यवस्था की साइज को दर्शाता है। साथ–साथ आयातों को जीडीपी से घटाया जाता है।

इन चारों स्त्रोतों से उत्पन्न हुये जीडीपी की गणना करने के लिये पहले वस्तुओं की सूची बनाई जाती है। फिर सर्वे करके इनकी प्रति परिवार या उद्यम मात्रा का अनुमान लगाया जााता है फिर परिवार अथवा उद्यम की संख्या से गुणा करके जीडीपी का आकलन किया जाता है। इस सूची को 5–10 वर्ष के बाद नया बनाया जाता है। समय–समय पर नई वस्तुओं की खपत शुरु हो जाती है। जैसे पिछले 20 वर्षों में मोबाइल फोन की खपत बड़ी मात्रा में होने लगी है। वर्ष 1995 में बनाई गई सूची में मोबाइल फोन नहीं होगा। यदि आज की जीडीपी गणना 1995 की सूची के आधार पर की जाती है तो मोबाइल की खपत छूट जाती है। इस क्रम में हाल में सरकार ने जीडीपी का नया फार्मूला बनाया है।

साथ–साथ सरकार ने एक और परिवर्तन किया है। अब तक जीडीपी की गणना वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर की जाती थी। जैसे मोबाइल फोन के उत्पादन में कितना तार, प्लास्टिक, कांच, साफ्टवेयर तथा श्रम लगा इसे मापा जाता था। अब सरकार ने वस्तुओं के बाजार भाव के आधार पर जीडीपी की गणना करने का निर्णय लिया है। बाजार भाव में उत्पादन कम्पनी का प्राफिट तथा रिटेलर का मार्जिन भी शामिल होता है। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बाजार भाव से ही जीडीपी की गणना की जाती है। इस परिवर्तन के कारण देश का जीडीपी 15–20 प्रतिशत बढ़ गया होगा ऐसा मेरा अनुमान है।

जीडीपी की गणना के कई पेंच हैं। सरकार द्वारा खपत, निवेश तथा निर्यात् की मात्रा का विभिन्न तरीकों से अनुमान लगाया जाता है। इस अनुमान का आधार पारदर्शी नहीं होता है। सेक्शन आफीसर द्वारा इन्हें आसानी से बढ़ाया घटाया जा सकता है। वर्तमान में जीडीपी में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि को समझने के लिये अर्थव्यवस्था के दूसरे आंकड़ों को देखना होगा। वर्तमान समय में तमाम सूचकांक निगेटिव हैं।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछली तिमाही में बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में केवल 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी। पिछले साल इसी तिमाही में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी। इसी क्रम में उद्योगों को दिये गये ऋण में पिछली तिमाही में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी जबकि पिछले वर्ष 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी।

बैंकों द्वारा कम मात्रा में ऋण दिया जाना इस बात का संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था में चाल नहीं है। फिर जीडीपी में तेजी कैसे आ सकती है?

बम्बई स्टाक इक्सचेंज के सेंसेक्स सूचकांक में शामिल बड़े उद्योगों में पिछली तिमाही के रिजल्ट कमजोर रहे हैं। लारसन एण्ड ट्यूबरो, सन फार्मा, तथा महिन्द्रा एण्ड महिन्द्र के के शुद्ध लाभ में क्रमशः 27 प्रतिशत, 44 प्रतिशत, एवं 39 प्रतिशत की गिरावट आयी है। जानकारों की माने तो लगभग यही गति दूसरी कम्पनियों की भी रही है।

जीडीपी का एक प्रमुख हिस्सा सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा सरकारी सेवाओं का होता है जैसे पुलिस, नोट छापना, रक्षा आदि के लिये किये गये कार्य। सरकारी सेवा क्षेत्र में पिछली तिमाही में मात्र 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के लिये सरकार ने खर्च करने बन्द कर दिए हैं। इस प्रकार के दूसरे आंकड़े भी उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ रही है। ऐसे में सरकार द्वारा किय जा रहा 7.5 प्रतिशत की विकास दर का दावा संदिग्ध है। याद करें कि अक्टूबर से दिसम्बर 2014 के जीडीपी के आंकड़े पहले 7.5 प्रतिशत वृद्धि के बताये गये थे। बाद में इन्हें 6.6 प्रतिशत पर रिवाइज कर दिया गया था। संभावना है कि पिछली तिमाही के आंकड़ों को इसी प्रकार रिवाइज करके घटा दिया जायेगा। ❑

विश्लेषण

मानसून पर निर्भर है देश की अर्थव्यवस्था

हमें याद रखना होगा कि अलनीनो से देश के प्रभावित हिस्से वही हैं जहां कृषि वर्षा पर अधिक निर्भर है। कमजोर मानसून से ग्रामीण इलाकों की खरीद क्षमता में कमी आ जाएगी। यह बात ग्रामीण क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित करेगी। यह भी ध्यान रखना होगा कि पिछले वर्ष कम बारिश के बावजूद खाद्यान्न व अन्य पदार्थो की कीमतें कम बनी रहीं, लेकिन इस बार कीमतें बढ़ने की आशंका है।

■ जयंतीलाल भंडारी

आज देश के किसान लगातार मौसम की खराबी का खमियाजा भुगतते–भुगतते हताश दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हाल ही में भारतीय मौसम विभाग (आईएमडीओ) के साथ–साथ ऑस्ट्रेलियन वेदर ब्यूरो (एडबल्यूबी) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि अलनीनो के भारत आने की आशंका सामान्य से तीन गुना ज्यादा है। अलनीनो के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत में होने वाली बारिश सामान्य की तुलना में 93 से 85 प्रतिशत रह सकती है।

वस्तुतः अलनीनो उस समुद्री घटना का नाम है जब प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के अत्यधिक गरम होने और वायुमंडलीय परिस्थितियों में बदलाव होने से नियंतत्र वष क्षेत्र बदल जाते हैं। अलनीनो के कारण नियंत्रण वर्षा क्षेत्र अस्त–व्यस्त होने से भारत के मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लगातार दूसरे साल मानसून कमजोर रहने पर देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश में छह से सात फीसद तक की कमी देखने को मिल सकती है। इसमें भारत के वे इलाके शामिल हैं जो कृषि के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात की खेती काफी हद तक मानसून पर निर्भर होती है। इन प्रदेशों में अलनीनो का ज्यादा असर हो सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून न केवल खरीफ की फसल पर प्रत्यक्ष रूप से असर डालता है बल्कि रबी की फसल को भी प्रभावित करता है।

गौरतलब है कि भारत में बारिश और अर्थव्यवस्था का जटिल रिश्ता बना हुआ है। देश की कुल कृषि भूमि में 60 फीसद से अधिक पर नियमित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ की फसल का लगभग आधा योगदान रहता है। धान, कपास, सोयाबीन, जूट, मूंगफली इत्यादि खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, जिनकी बुआई जून में शुरू हो जाती है और कटाई का सिलसिला सितम्बर से शुरू होता है। चूंकि इस वर्ष अलनीनो प्रभाव की आशंका है, लिहाजा बारिश की कमी की संभावना बने रहना तय है। इस परिदृश्य ने मानसून से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक चिंताओं को जन्म दे दिया है। बारिश और खाद्यान्न उत्पादन का कीमतों से सीधा संबंध है।

कम बारिश और उच्च महंगाई का रिश्ता स्पष्ट दिखाई देता है। चूंकि देश के 14 करोड़ से अधिक परिवार खेती पर निर्भर हैं, अतः कम बारिश की स्थिति में खेती–किसानी से जुड़े अधिकांश छोटे किसानों का जीवन सबसे अधिक प्रभावित होता है। देश में किसानों की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है।

अप्रैल 2015 में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह द्वारा यह ऐलान किया गया कि किसानों से कर्ज वसूली को एक साल के लिए टाल दिया है। इससे देश में कृषि संकट का अनुमान लगा सकते

हैं। ऐसे मे कम बारिश से किसानों की स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। खासतौर से ऐसे किसान जिन्हें कृषि के लिए संस्थागत ऋण और अन्य सुविधाओं का लाभ संतोषप्रद रूप से नहीं मिला है, उनकी मुश्किलें कम बारिश से और बढ़ जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई के आंकड़ों पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के शोधार्थियों द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि कुल कृषि ऋण का 30 फीसद से भी कम बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा जारी किया जाता है। इसी तरह एनएसएसओ की वर्ष 2013 के लिए जारी अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि ग्रामीण परिवारों के कुल बकाया ऋणों में तकरीबन 44 फीसद असंगठित क्षेत्र के थे। इसमें भी चिंताजनक बात यह थी कि 33 फीसद से अधिक कर्ज साहूकारों से लिया गया था।

इस वर्ष कमजोर मानसून रहने पर इस संभावना को भी आघात लगेगा कि रबी की फसल में हुए नुकसान की भरपाई खरीफ के मौसम में भारी पैदावार के जरिये की जा सकती है। इस वजह से अधिकांश कृषि जिंसों की आपूर्त्ति और मूल्य पर असर पड़ेगा। खासतौर पर मोटे अनाज, दालों, तिलहन, सब्जियों, फल एवं पालतू पशुओं से मिलने वाले उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं।

15 अप्रैल से 15 मई, 2015 से संबंधित वायदा कारोबार के आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादातर कृषि जिंसों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। कई महत्वपूर्ण उद्योग जैसे सोयाबीन, टेक्सटाइल, शक्कर मिल, दाल मिल आदि सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं, जबकि कई उद्योगों को अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि उत्पादों की जरूरत होती है। ऐसे कृषि आधारित उद्योगों के उत्पाद महंगे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, खराब मानसून के कारण सरकार का ध्यान कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित हो सकता है, जिसका असर आर्थिक सुधारों तथा विकास संबंधी अन्य पहल पर पड़ सकता है।

कम बारिश और उच्च महंगाई का रिश्ता स्पष्ट दिखाई देता है। चूंकि देश के 14 करोड़ से अधिक परिवार खेती पर निर्भर हैं, अतः कम बारिश की स्थिति में खेती–किसानी से जुड़े अधिकांश छोटे किसानों का जीवन सबसे अधिक प्रभावित होता है। देश में किसानों की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है। अप्रैल 2015 में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह द्वारा यह ऐलान किया गया कि किसानों से कर्ज वसूली को एक साल के लिए टाल दिया है। इससे देश में कृषि संकट का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे मे कम बारिश से किसानों की स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस वर्ष कमजोर मानसून का आकलन सही साबित होता है तो चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर के 7.9 फीसद के अनुमान में कमी आएगी। देश में मानसून के कमजोर होने की आशंका के मद्देनजर केंद्र और राज्य, दोनों को सतर्क रहना होगा और आकस्मिक फसल योजना की पूरी तैयारी रखनी होगी। सूखा प्रबंधन कौशल का इस साल पुनः उपयोग करना होगा। फसल में अपर्याप्त आर्द्रता और उत्पादन में कमी से निपटने के उपायों पर अधिक जोर देना होगा। फसल बुआई तथा कच्चे माल के इस्तेमाल में बदलाव लाना होगा। जल संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देना होगा। जिन इलाकों में अपर्याप्त नमी के कारण बुआई में देरी हो, वहां किसानों को ऐसी फसलों के बीज देने होंगे जो जल्द तैयार हो जाते हैं और जो देर से हुई बुआई के बावजूद उत्पादन के मोर्चे पर अच्छे परिणाम देते हैं।

हमें याद रखना होगा कि अलनीनो से देश के प्रभावित हिस्से वही हैं जहां कृषि वर्षा पर अधिक निर्भर है। कमजोर मानसून से ग्रामीण इलाकों की खरीद क्षमता में कमी आ जाएगी। यह बात ग्रामीण क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित करेगी। यह भी ध्यान रखना होगा कि पिछले वर्ष कम बारिश के बावजूद खाद्यान्न व अन्य पदार्थो की कीमतें कम बनी रहीं, लेकिन इस बार कीमतें बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बारिश की कमी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की निराशा बढ़ेगी। उनके लिए रोजगार के रणनीतिक प्रयास जरूरी होंगे।

उम्मीद है कि अपर्याप्त मानसूनी बारिश की मुश्किलों से निपटने के लिए सरकार अपनी प्रबंधन क्षमता का सफल परिचय देगी और भविष्य में प्रयास करेगी कि देश की कृषि मानसून का जुआ ही न बनी रहे। इस हेतु अर्थव्यवस्था को मानसून से सुरक्षित किए जाने को नीतिगत लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। ❑

कृषि

समितियों का सिलसिला की जगह अन्नदाता पर दें ध्यान

जटिल और परेशान करने वाले भारतीय कृषि संकट का समाधान अमेरिका या चीन में नहीं है। यह सही समय है जब हम विकसित देशों के उदाहरण देना बंद कर दें जिनकी बात सिर्फ नई और महंगी कृषि मशीनरी और औजार के आयात पर आकर समाप्त हो जाती है। समाधान हमें अपनी जमीन पर खोजने होंगे।

■ देविन्दर शर्मा

पिछले कुछ दशकों में किसानों की आत्महत्याओं पर 53 विशेषज्ञ समितियों ने रिपोर्टें सौंपी हैं, लेकिन मौतों की श्रृंखला बिना रुके जारी है। इतने विशेषज्ञों की सलाह के बावजूद पिछले बीस साल में करीब तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है। इस हिसाब से देश के किसी न किसी हिस्से में हर घंटे दो किसान खुदकुशी कर लेते हैं।

इस मुद्दे पर और न जाने कितनी समितियां गठित की जाएंगी, लेकिन इस बीच यह तो साफ होता जा रहा है कि

इन विशेषज्ञों ने भी अपने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। लगातार जारी और गहराते जा रहे कृषि संकट को दूर करने के लिए कुछ नए तरीके खोजने के लिए पंजाब किसान आयोग द्वारा आयोजित विचार–विमर्श भी किसी 'अलग तरीके का' समाधान निकालने में विफल रहा। कुछ रूटीन सलाहों के अतिरिक्त उनके पास देने को कुछ नहीं था।

इससे मुझे कुछ हफ्ते पहले की एक खबर का ध्यान आता है जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खडसे ने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि राज्य सरकार को इस बारे में रास्ता नहीं सूझ रहा कि वह विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्या किस तरह रोके। इस तरह की मायूसी का भाव ऐसे वक्त में है जब नीति आयोग ने कृषि पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है और राज्य सरकारों को भी इसी तरह के टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं।

मैं नहीं जानता कि कृषि पर टास्क फोर्स की क्या जरूरत है जब नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पानगड़िया ने नीति आयोग की वेबसाइट पर अपने शुरुआती उद्‌बोधन में कृषि संकट के समाधान को लेकर अपने विचार पहले ही व्यक्त कर दिए हैं।

वह चाहते हैं कि किसानी करने वाली आबादी के बड़े हिस्से को कृषि कार्य से बाहर कर दिया जाना चाहिए। चाहे वह कितना भी गलत हो, लेकिन रोडमैप बना लिया गया है और ऐसे में मुझे ताज्जुब है कि केंद्रीय और राज्य स्तरों पर बनाए जाने वाले अनगिनत टास्क फोर्स से क्या हासिल करने की अपेक्षा की जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब कृषि संकट का समाधान ढूंढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पहले भी और पूर्ववर्ती योजना आयोग ने कई साल अनगिनत विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। इसी तरह पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने विशेषज्ञों से विचार–विमर्श की श्रृंखला के बाद कृषि नीति दस्तावेज तैयार किए। 12वीं योजना के दस्तावेज की तैयारी में भी दीर्घकालिक कृषि, तकनालॉजी, पानी और मार्केटिंग पर कई टास्क फोर्स और समितियों ने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। इस बीच कृषि संकट का और गंभीर होना जारी ही रहा।

संकट के लिए जिम्मेदार लोगों से ही किसी विश्वसनीय समाधान की अपेक्षा

नहीं की जा सकती। ज्यादातर विश्वसनीय समितियों और पैनलों में वरिष्ठ नौकरशाह, कृषि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और वरिष्ठ कृषि अधिकारी होते हैं जो किसी न किसी तरह उस व्यवस्था के हिस्से होते हैं जिसने संकट इस हद तक उत्पन्न किया है। इसलिए उनसे 'अलग हटकर' समाधान देने की अपेक्षा व्यर्थ की आशा करना है। अगर 53 विशेषज्ञ समितियां विफल हो चुकी हैं तो यह सोचना बेकार है कि केंद्रीय और राज्यों के स्तर पर देश भर में गठित 30 और टास्क फोर्स किसी उद्देश्य को पूरा करेंगे।

यह वही है जिसके बारे में अल्बर्ट आइन्स्टीन ने हमें चेताया था। उन्होंने कहा था, 'हम उसी तरह सोचकर अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते जैसे हमने इसे पैदा किया था।' वह बिल्कुल सही थे। जो बात नहीं स्वीकार की जा रही है, वह यह है कि वर्तमान कृषि संकट उसी तरह की नीतियों और दृष्टिकोणों का परिणाम है जिनके जरिये दुर्भाग्यवश हम उत्तर ढूंढ़ने की अब कोशिश कर रहे हैं।

नियमित तौर पर सुझाए जाने वाले ये अव्यावहारिक समाधान वर्तमान कृषि उपज पैटर्न के दायरे में आते हैं। कुछ गेहूं से मक्के की तरफ शिफ्ट करने जैसी उपज की विविधता की सलाह देते हैं, कुछ आय बढ़ाने के लिए कृषि संरक्षण का सुझाव देते हैं, कुछ अन्य बाजार नियंत्रित हस्तक्षेप की बात करते हैं और अंततः सभी फसल उत्पादन बढ़ाने की जरूरत की बात करते हैं। ये सभी विकल्प अमेरिका, यूरोप और चीन में आजमाए जा चुक हैं। और कृषि कार्यों को शक्ति देने के लिए अमेरिका–यूरोप में अब भी एक अरब रोजाना से अधिक कृषि सब्सिडी दी जा रही। इस सब्सिडी की वापसी का मतलब विकसित देशों में हाइटेक कृषि का ढह जाना होगा। भारत में ज्यादा परिष्कृत और महंगी मशीनरी को लागू करना सीधे–सीधे किसानों के कर्ज जाल को और बढ़ाना है। पंजाब में जिस तरह टेक्नोलॉजी आधारित समाधान पर जोर दिया गया, उस तरह के समाधान से कृषि संकट और गंभीर ही हो गया। पंजाब जो प्रमुख कृषि राज्य है, वहां किसी न किसी इलाके में रोजाना दो किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

करीब तीन दशकों से भारत का ग्रामीण समाज ढह रहा है। रासायनिक उर्वरकों के बहुत ज्यादा उपयोग ने हरी–भरी जमीन को विषैला बना दिया है, जल दोहन ने भूगर्भ जल को इस हद तक सुखा दिया है कि बंजर का विस्तार हो रहा है और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। साल दर साल लागत मूल्य बढ़ते जाने और उत्पादन मूल्य स्थिर रहने से किसान उन्हीं आर्थिक नीतियों के शिकार बन गए हैं जिसने उन्हें देश के नायक के तौर पर बताया था। कृषि न सिर्फ न किए जाने लायक, बल्कि आर्थिक रूप से अलाभकारी हो गई है। क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी के उपयोग से किसानों की आय बढ़ी है? मैंने प्रगतिशील माने जाने वाले पंजाब के उन किसानों की लागत और मूल्य का आकलन किया है जो नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और जिन्हें 99 प्रतिशत सुनिश्चित सिंचाई प्राप्त है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की नवीनतम रिपोर्ट प्रति हेक्टेयर गेहूं और चावल का औसत शुद्ध प्रतिफल 36,052 रुपये और 3029 रुपये मासिक बताती है। नई टेक्नोलॉजी या मशीनी उपकरण बेचे बिना उनकी कृषि आय को बढ़ाने के लिए नीति की योजना में भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण की जरूरत है। इसके लिए दो तात्कालिक कदमों की अपेक्षा है।

पहला – कृषि पर आम तौर पर निगाह रखने वाले विशेषज्ञों को अलग करना। हमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की जरूरत है जो इस पर सोचें और भिन्न तरीके से योजना बनाएं। संकट के नियंत्रण में लगे लोगों का समान समूह कोई अर्थकारी सुझाव देगा, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। टास्क फोर्स की संरचना देखने पर मेरी चिंता यह है कि नीति आयोग के सुझाव वर्तमान संकट को और गहरा ही करेंगे। आइंस्टीन गलत नहीं थे।

दूसरे – जटिल और परेशान करने वाले भारतीय कृषि संकट का समाधान अमेरिका या चीन में नहीं है। यह सही समय है जब हम विकसित देशों के उदाहरण देना बंद कर दें जिनकी बात सिर्फ नई और महंगी कृषि मशीनरी और औजार के आयात पर आकर समाप्त हो जाती है। समाधान हमें अपनी जमीन पर खोजने होंगे।

अगर हम ध्यान से अपने यहां देखेंगे और कृषि–पर्यावरणीय क्षेत्र की खास जरूरतों को पूरा करने वाले स्थानीय समाधानों की खोज करेंगे तो हमें दीर्घकालिक कृषि सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले चिरस्थायी उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाला समाधान महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करता है, लेकिन असली बात यह होनी चाहिए कि किसानों को किस तरह निश्चित मासिक आय उपलब्ध हो। ❑

रूक सकती हैं किसान आत्महत्याएं

किसान अन्नदाता है, इसलिए उसे मरने पर मजबूर करने की बजाए उसे उसकी उपज का सही मूल्य दिलाना, यह सरकार का दायित्व है। किसान की आमदनी सुनिश्चित हो, इसका भी प्रयास होना चाहिए। उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हुए उसकी लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर देना चाहिए। अगर जरूरी हो तो उपज का मूल्य कम करने वाले आयातों पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए। गांवों में छोटे उद्योग लगाकर किसान और खेतीहर मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध हों। ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि किसान को भरपूर आमदनी हो ताकि उसे कर्ज लेने की जरूरत ही न पड़े। हाथ पर हाथ धरे रहने से सरकार मजबूर ही रहेगी।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

हाल ही में महाराष्ट्र के एक मंत्री ने यह कहा कि उनकी सरकार के पास किसान आत्महत्याओं को रोकने की कोई नीतियां या तरीका नहीं है। गौरतलब है कि किसान आत्महत्याओं की शुरूआत महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हुई और उसके बाद यह प्रवृत्ति आंध्र प्रदेष, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत देश के कई दूसरे क्षेत्रों में फैलती चली गई और अभी तक किसान आत्महत्याओं की संख्या देश भर में सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो 3 लाख लेकिन गैरसरकारी अनुमानों के अनुसार 10 लाख तक पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी 'विदर्भ' किसान आत्महत्याओं का मुख्य केन्द्र बना हुआ है।

नहीं हैं वैकल्पिक रोजगार

भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है और केन्द्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का 55 प्रतिशत से ज्यादा कृषि पर निर्भर करता है। कुल कार्यशील जनसंख्या जो कृषि में लगी है उसमें 25 प्रतिशत किसान हैं जो अपनी भूमि पर खेती करते हैं, और शेष 30 प्रतिशत भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं।

आज जबकि खेती में लगे लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, हांलाकि आजादी के बाद से अब तक कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 70 प्रतिशत से घटकर 55 प्रतिशत ही पहुंचा है लेकिन कृषि की कुल जीडीपी में भागीदारी 1950–51 में 56.5 प्रतिशत से घटकर अभी तक मात्र 14 प्रतिशत ही रह गई है। यानि शेष अर्थव्यवस्था, जिसमें मात्र 45 प्रतिशत ही कार्यशील जनसंख्या है, वो अब जीडीपी का 86 प्रतिशत प्राप्त करती है। यह तथ्य किसानों और कृषि पर आश्रित अन्य लोगों की दुर्दशा को बयान करता है। माना जाता है कि विकास के रास्ते पर उद्योगों और सेवा क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ने की गति ज्यादा तेज होती है। इसलिए कृषि पर कार्यशील जनसंख्या की निर्भरता को कम करते हुए हम कृषि पर आश्रित लोगों की दशा में सुधार कर सकते हैं।

लेकिन आजादी के 68 वर्ष बीतने वाले हैं, लेकिन उद्योगों और सेवाओं में अभी भी हम रोजगार के इतने अवसर दिला नहीं पाये कि हम कृषि पर आश्रितों (खास तौर पर भूमिहीन खेतीहर मजदूरों) को अन्य रोजगार प्रदान कर पायें। वैकल्पिक रोजगार के अभाव में वे अभी भी कृषि पर ही आश्रित हैं, और उनकी आमदनी सुनिश्चित करने के लिए पिछले लगभग 5 दशकों से हजारों करोड़ रूपया हर वर्ष रोजगार मूलक कार्यक्रमों पर सरकार को खर्च करना पड़ रहा है।

ऐसा माना जाता है कि औसतन 3 किसान रोज आत्महत्यायें करते हैं। इस विषय के अध्ययन और समाधान के उपाय सुझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई कमेटियां का गठन किया। सभी अध्ययनों की रिपोर्टों में एक बात समान है कि किसान आत्महत्याओं का मुख्य कारण उनकी भारी कर्जदारी है।

विदर्भ में किसानों की आत्महत्याएं

ऐसा माना जाता है कि औसतन 3

किसान रोज आत्महत्यायें करते हैं। इस विषय के अध्ययन और समाधान के उपाय सुझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई कमेटियां का गठन किया। सभी अध्ययनों की रिपोर्टों में एक बात समान है कि किसान आत्महत्याओं का मुख्य कारण उनकी भारी कर्जदारी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की 59वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की कर्जदारी का मुख्य कारण खेती के लिए लिये गए ऋण हैं। प्रश्न यह है कि दो दशक पहले किसान आत्महत्याएं नहीं करते थे, लेकिन अब किसान भारी मात्रा में आत्महत्याएं कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर किसान वे हैं जो कपास की खेती करते है।

गौरतलब है कि विदर्भ की भूमि कपास की खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त है। विदर्भ का किसान अपने खाने के लिए खाद्यान्न की खेती करता था और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए साथ ही साथ कपास की खेती भी करता था। एक क्विंटल कपास बेचकर उससे जितने पैसे मिलते थे, उससे वह 12 ग्राम सोना खरीद सकता था। लेकिन हालात बदल गए आज विदर्भ के अधिकतर किसान केवल कपास का उत्पादन करते हैं और कपास का दाम लगभग स्थिर है जबकि किसान की बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य आगतों की कीमते पहले से 4 से 6 गुणा हो गई है।

आज डब्ल्यूटीओ समझौतों के कारण विदेशों से कपास का भारी आयात हो रहा है। 1994 में कपास की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1.1 डॉलर से घटकर मात्र 50 सेंट रह गई है। देश में इस कारण कपास की कीमतें बढ़ नहीं पाई और पिछली फसल के दौरान किसान को प्रति क्विंटल औसतन मात्र 3600 से 3900 रूपये ही प्राप्त हुए। आज एक क्विंटल कपास बेच कर वह 1. 5 ग्राम भी सोना नहीं खरीद सकता। कृषि लागते ही नहीं किसान की जीवन लागत भी लगातार बढ़ती गई, जबकि कृषि अलाभकारी होती गई।

यही नहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने बीजों को बेचने के लिए किसान को गुमराह करती रही। गौरतलब है कि विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित बी.टी. कपास का बीज जिसकी उत्पादन लागत तो मात्र 20 रूपये प्रति पैकेट है, देश में ये कंपनियां उसे 900 से 1000 रूपये प्रति पैकेट बेच रही है। लाभ कमाने के लिए वो किसानों को यह भी नहीं बता रही कि ये बीज केवल सिंचित भूमि के लिए उपयुक्त हैं। ऐसे में वर्षा न होने पर तमाम लागत लगाने पर भी फसल नष्ट हो जाती है और किसान को भारी नुकसान होता है। यह भी किसान आत्महत्याओं का मुख्य कारण बना हुआ है।

अन्य किसानों को भी नहीं मिलता उचित मूल्य

यह खुला सत्य है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता।

भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल चुनावी वादा किया था कि किसान को उसकी कुल लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम मूल्य उपलब्ध कराया जायेगा। अभी तक वह चुनावी वायदा मात्र जुमला ही बनकर रह गया है। पिछले कुछ समय से शेष अर्थव्यवस्था में बढ़ती आमदनियों, बदलती खाने–पीने की आदतों इत्यादि के चलते फल–सब्जियों की बढ़ती कीमतों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण किसान की आमदनी में मामूली वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन आमदनी में यह वृद्धि सभी किसानों के लिए नहीं है।

किसानों ने खुद बढ़ाई अपनी आमदनी

किसान अक्सर अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए बागवानी और पशुपालन भी कर लेते हैं। पिछले कुछ समय से देश के कुछ हिस्सों, खासतौर पर पश्चिमी भारत के राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि) में पशुपालन के माध्यम से अपनी आमदनी में वृद्धि की हैं।

आज देश में दुग्ध उत्पादन 4 लाख करोड़ रूपए का है, जो किसी भी फसल से ज्यादा है। देखने में आया है कि गुजरात के गांवों में दुग्ध उत्पादन के बढ़ने से खुशहाली आई है।

रूक सकती है किसान आत्महत्याएं

सरकार में बैठे लोग स्वयं को मजबूर न मानते हुए यदि उचित प्रयास करे तो किसान आत्महत्याएं जरूर रूक सकती है। किसान अन्नदाता है, इसलिए उसे मरने पर मजबूर करने की बजाए उसे उसकी उपज का सही मूल्य दिलाना, यह सरकार का दायित्व है। किसान की आमदनी सुनिश्चित हो, इसका भी प्रयास होना चाहिए। उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हुए उसकी लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर देना चाहिए। अगर जरूरी हो तो उपज का मूल्य कम करने वाले आयातों पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए। गांवों में छोटे उद्योग लगाकर किसान और खेतीहर मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध हों। ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि किसान को भरपूर आमदनी हो ताकि उसे कर्ज लेने की जरूरत ही न पड़े। हाथ पर हाथ धरे रहने से सरकार मजबूर ही रहेगी। ❑

रपट

भारत में अब मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक बाय इंडिया की तर्ज पर कार्य करना होगा : कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच की ओर से बीते मई माह को मल्केश्वर मठ में विचार व्याख्यानमाला कार्यक्रम का आयोजन जालोर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष मोहन पाराशर की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके लघु भारती के जिलाध्यक्ष दामोदर भूतड़ा व विशिष्ठ अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरीलाल जी ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में अब मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक बाय इंडिया की तर्ज पर कार्य करना होगा। तभी भारतीयों के लिए तकनीकी व अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ पाएंगे और हमारा भारत आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकेगा।

उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि भारतीयों की ओर से बाहरी कंपनियों के सॉफ्ट ड्रिंग्स का सेवन करने से इन कंपनियों द्वारा भारत में कमाया गया सारा लाभ विदेशों में जा रहा है। साथ ही चायना के माल की आवक होने से भारतीय उद्योग धंधे भी खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें अपने पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए शीतल पेय के रूप में घरेलू शहद, नीम्बू व दही समेत अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।

हमें अपने पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए शीतल पेय के रूप में घरेलू शहद, नीम्बू व दही समेत अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।

उन्होंने प्रत्येक परिवार को तोड़ने वाले टीवी सीरियल को अपने बच्चों को दिखाने के बजाय सामूहिक परिवार में रहकर बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में बताने की आवश्यकता जताई।

कार्यक्रम के दौरान मंच के राष्ट्रीय संगठक ने प्रत्येक परिवार को स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का आह्वान करते हुए कहा कि मंच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जेनेटिकल मोडिफाइड फसलों के बीजों की खुले वातावरण में परीक्षण पर रोक लगाने व विदेशी कंपनियों को इसके लाइसेंस की अनुमति नहीं देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासत रहा है। मंच के विरोध व आन्दोलन के कारण ही भारत सरकार की ओर से कई जेनेटिकल मोडिफाइड फसलों के बीजों को खुले वातावरण में परीक्षण पर रोक लगाई गई है।

कार्यक्रम में राजस्थान प्रांत के सहसंयोजक धर्मेंद दुबे द्वरा जिला कार्यकारिणीयों के नवीन पदों की घोषणा भी की गई।

मंच संचालन डॉ. दीपक श्रीमाली व पूजा शर्मा द्वारा किया गया। युवा जितेन्द्र शर्मा की ओर से राष्ट्रसेवा पर गीत की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में तरुण गहतोल, जुगलकिशोर दवे, अनिल, मयंक देवड़ा व विनायक ने सहयोग दिया। कार्यक्रम में जिले के सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, कृषि समिति के सदस्य, शिक्षक, व्यापारी, महिला संगठन व स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भाग लिया। ❑

(अन्य रपट पृष्ठ 38 पर जारी)

ग्राम अंचल में आधार प्रदर्शन

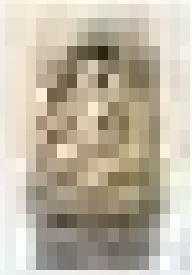

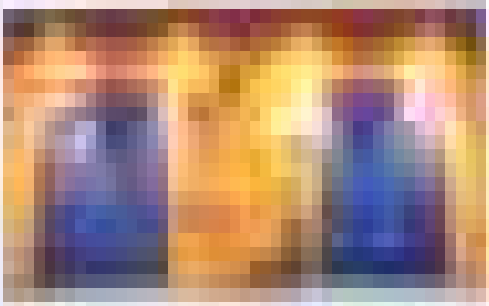

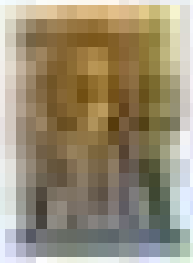

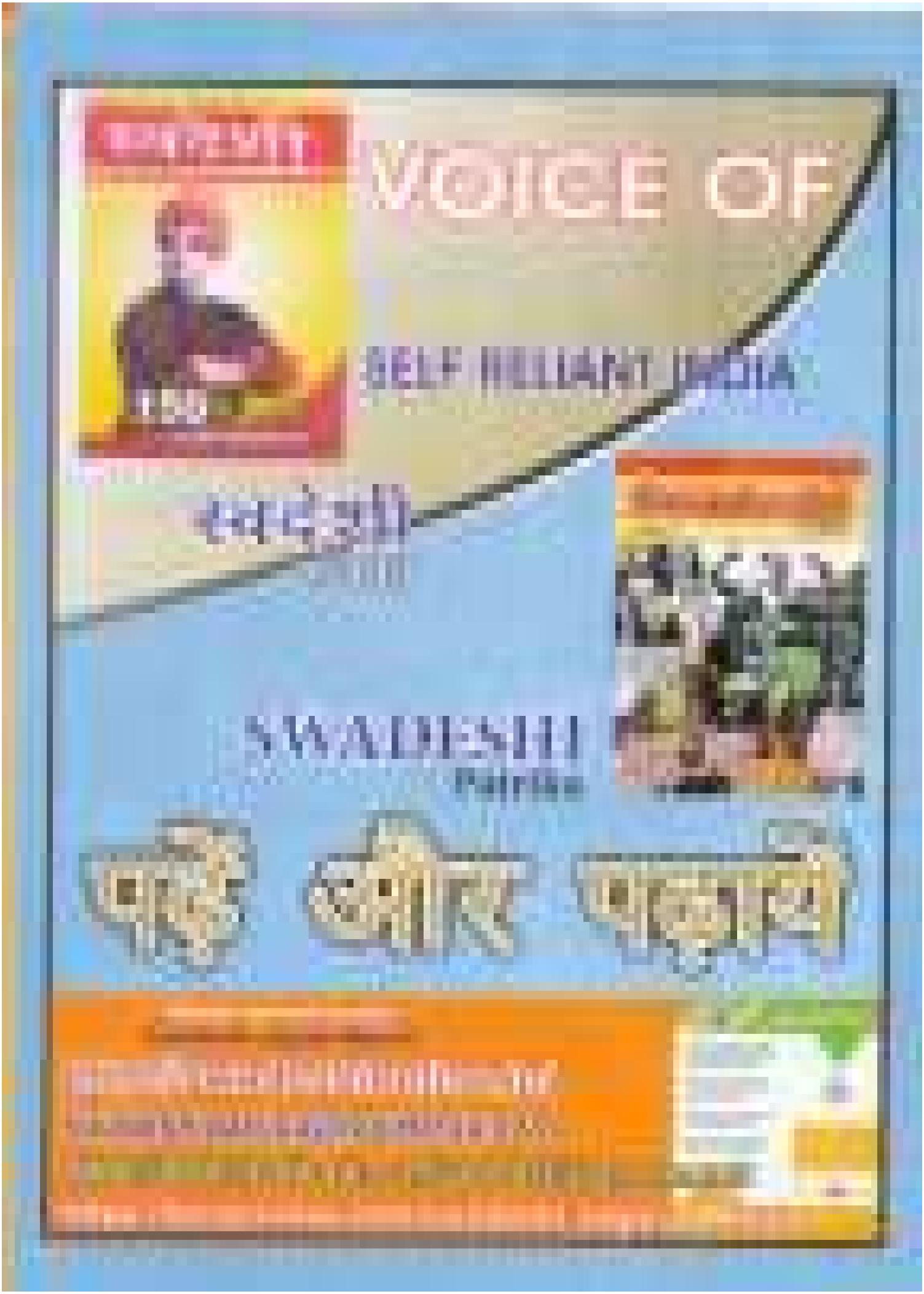

VOICE OF
SELF RELIANT INDIA
स्वदेशी
SWADESHI
Patrika

समस्या

जहरीले दूध के कारोबार पर लगे रोक

देश के लगभग सभी हिस्सों में मिलावटी दूध का गोरखधंधा कई सालों से बदस्तूर चल रहा है। अधिक मुनाफा कमाने की चाहत में दूध कारोबारी सीधे–सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि मिलावटी दूध के सेवन से न केवल लोग बीमार हो रहे हैं, बल्कि किडनी, लीवर व हार्ट फेल जैसे मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके इस्तेमाल से कैंसर होने की भी प्रबल आशंका रहती है। जिन विभागों या लोगों पर मिलावटी दूध के गोरखधंधे को रोकने की जिम्मेदारी है, वे पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं।

■ शशांक द्विवेदी

कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध मामले में कहा था कि क्या दूध में सायनाइड मिलाया जाए, जिसे पीकर लोग तुरंत मरने लगे, तब सरकार कोई कानून बनाएगी। लेकिन इस तल्ख टिप्पणी के बावजूद जमीनी हालात जस के तस हैं। शायद अब मिलावटी दूध पीना देश में लोगों की नियति ही बन गई है।

आंकड़ों के साथ–साथ खुद केंद्र सरकार अब संसद में इसकी सचाई को स्वीकार कर रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के देशभर में कराए सर्वेक्षण में दूध के 68.4 प्रतिशत नमूने मिलावटी पाए गए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाने पर इन सभी को 33 राज्यों से हटा लिया गया है। पिछले दिनों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बताया कि एफएसएसएआई के पांच क्षेत्रीय कार्यालयों में कराए गए सर्वेक्षण के तहत 33 राज्यों से 1791 नमूने लिए गए थे जिनका परीक्षण सरकारी लैब में किया गया और इनमें मिलावट पाई गई।

श्री नड्डा ने बताया कि वसामुक्त दूध पाउडर के 548 नमूने (44.69 प्रतिशत) भी खराब पाए गए। इनमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक पाई गई। देश में कई सालों से चल रहे मिलावटी दूध के कारोबार को लेकर कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाते हुए इस मामले में उदासीन रवैया रखने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। न्यायमूर्ति एमवाई इकबाल और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की खंडपीठ ने मिलावटी दूध के कारोबार पर रोक लगा पाने में केंद्र और राज्य सरकारों की निष्क्रियता पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि क्या दूध में सायनाइड मिलाया जाए जिसे पीकर लोग तुरंत मरने लगे, तब सरकार कोई कानून बनाएगी? लेकिन इतनी तल्ख टिप्पणी सुनने के बाद भी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इतने अहम और संवेदनशील मुद्दे पर सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

देखा जाए तो आज दूध में केमिकल की मिलावट ने दूध की गुणवत्ता खत्म कर दी है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लीवर एवं किडनी फेल होने जैसी जानलेवा बीमारियां भी केमिकल मिले दूध के कारण बढ़ रही हैं। वहीं अगर दूध में यूरिया आदि की मिलावट है तो मरीज को खून की उल्टी, लकवा या फिर अधिक गंभीर परिस्थिति में उसकी मौत भी हो सकती है।

देखा जाए तो आज दूध में केमिकल की मिलावट ने दूध की गुणवत्ता खत्म कर दी है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लीवर एवं किडनी फेल होने जैसी जानलेवा बीमारियां भी केमिकल मिले दूध के कारण बढ़ रही हैं। वहीं अगर दूध में यूरिया आदि की मिलावट है तो मरीज को खून की उल्टी, लकवा या फिर अधिक गंभीर परिस्थिति में उसकी मौत भी हो सकती है। व्यावसायिक रूप में गाय–भैंस पालने वालों से लेकर दूधिए और ठेकेदार, सभी दूध की गुणवत्ता से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बावजूद केन्द्र और राज्य सरकारों के खाद्य एवं स्वास्य विभाग ने इसे रोकने को लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए हैं।

सच बात तो यह है कि लोगों की सेहत से जुड़ा यह संवेदनशील मुद्दा सरकारों की प्राथमिकता सूची में ही नहीं है। दूध में मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए राज्य सरकारों को मौजूदा कानून में बदलाव करने के निर्देश दिए थे। लेकिन इस निर्देश पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अधिकांश प्रदेशों में अभी फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड एक्ट के तहत दोषी को अधिकतम छह माह कैद की व्यवस्था है। लचीले

कानून का लाभ मिलने से मिलावटखोरों की मानसिकता में बदलाव नहीं आ रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा कृत्रिम एवं मिलावटी दूध के कारोबार पर देशभर में किए गए सर्वे में 68.4 प्रतिशत दूध निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। इसमें 66 फीसद खुला दूध है। सिंथेटिक और मिलावटी दूध तथा दूध के उत्पाद यूरिया, डिटरजेंट, रिफाइंड ऑयल, कॉस्टिक सोडा और सफेद पेंट आदि से तैयार हो रहे हैं।

यह बताने की जरूरत नहीं कि यह सब मानव जीवन के लिए कितने घातक हैं, क्योंकि इनसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। नकली दूध बनाने के लिए रिफाइंड आयल एवं डिटर्जेंट लिक्विड का घोल तैयार किया जाता है। दूध में घी की मात्रा एवं आरएम वैल्यू बरकरार रखने के लिए केमिकल मिलाया जाता है। शुद्ध दूध की रिचर्ड मिशेल वैल्यू (आरएम) करीब 30 से 35 होनी चाहिए। कई बार केमिकलों से निर्मित दूध फैक्ट्रियों में खरीद के दौरान फैट एवं आरएम के मामले में शुद्ध दूध की तरह ही खरा उतरता है। लेकिन लोगों द्वारा इसे पीने के उपयोग में लेने से स्वास्थ्य एवं सेहत को भारी नुकसान पहुंचता है। नकली दूध को पानी में मिल्क पावडर मिलाकर बनाया जाता है। चिकनाई के लिए रिफाइन ऑयल व शैंपू का इस्तेमाल होता है। दूध में झाग बनाने के लिए वाशिंग पाउडर और सफेद रंग के लिए सफेदा मिलाया जाता है। दूध में मीठापन लाने के लिए ग्लूकोज का मिश्रण किया जाता है। इसी तरह कई और तरीकों और केमिकल की मदद से नकली या मिलावटी दूध बनाया जाता है।

देश के लगभग सभी हिस्सों में मिलावटी दूध का गोरखधंधा कई सालों से बदस्तूर चल रहा है। अधिक मुनाफा कमाने की चाहत में दूध कारोबारी सीधे–सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि मिलावटी दूध के सेवन से न केवल लोग बीमार हो रहे हैं, बल्कि किडनी, लीवर व हार्ट फेल जैसे मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके इस्तेमाल से कैंसर होने की भी प्रबल आशंका रहती है। जिन विभागों या लोगों पर मिलावटी दूध के गोरखधंधे को रोकने की जिम्मेदारी है, वे पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। इसका फायदा मिलावटी और जहरीले दूध के कारोबारी उठा रहे हैं।

ब्रांडेड डेयरी कंपनियों के दूध में भी कई बार शिकायतें आती हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में इसकी जांच नहीं हो पाती है। दूध में मिलावट के गोरखधंधे पर संसद में स्वास्थ्य मंत्री की स्वीकारोक्ति के बाद तो यह मामला और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि जब सरकार इसे मान रही है तो प्रश्न उठता है कि इसे रोकने को लेकर तत्काल कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?

बढ़ती जनसंख्या के सापेक्ष दूध की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी वजह से मिलावटी दूध बेचने वालों के लिए यह मोटे मुनाफे का कारोबार है। काली कमाई में संलिप्त लोग यह कभी नहीं सोचते कि कोई भी व्यक्ति दूध का सेवन स्वास्थ्य लाभ के लिए करता है, लेकिन उनके अनुचित मुनाफे का जरिया बना मिलावटी दूध लोगों को बड़े पैमाने पर मरीज बना रहा है। दूध में मिलावट को लेकर जमीनी स्तर पर पहले से तैयार खाद्य सुरक्षा कानून के पालन को लेकर कई खामियां हैं। मिलावटी दूध के मामले को लेकर अभी तक अधिकांश छोटे शहरों, जिलों में कोई जांच लैब नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर हो रही दूध की बिक्री के एवज में कस्बों और जिले के स्तर पर जांच संबंधी लैब न होने से कोई आम व्यक्ति दूध में मिलावट की शिकायत नहीं कर पाता है, क्योंकि शिकायत से लेकर जांच तथा उसके बाद सजा होने तक के प्रावधान की प्रक्रिया काफी लंबी है।

ब्रांडेड डेयरी कंपनियों के दूध में भी कई बार शिकायतें आती हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में इसकी जांच नहीं हो पाती है। दूध में मिलावट के गोरखधंधे पर संसद में स्वास्थ्य मंत्री की स्वीकारोक्ति के बाद तो यह मामला और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि जब सरकार इसे मान रही है तो प्रश्न उठता है कि इसे रोकने को लेकर तत्काल कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? कुल मिलाकर स्पष्ट जरूरत दिख रही है कि देशभर में मिलावटी दूध बेखौफ ढंग से संचालित हो रहे गोरखधंधे से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को ठोस नीति बनानी होगी। गांवों, कस्बों और शहरों में स्थानीय स्तर पर प्रशासन को इसके लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश और कड़े कानूनों का प्रावधान होना चाहिए। तभी मिलावटी दूध के कारोबार पर अंकुश लग पाएगा। ❑

मैगी प्रकरण के बहाने पर्यावरणीय प्रश्न

सीसे की अधिक मात्रा में उपस्थिति चाहे मैगी नूडल्स में हो अथवा हवा, पानी और मिट्टी में; सेहत के लिए नुकसानदेह तो वह सभी जगह है। जिस तरह किसी खाद्य पदार्थ के दूशित होने के कारण हम बीमार पड़ते अथवा मरते हैं, उसी तरह मिलावटी/असंतुलित रासायनिकी वाली मिट्टी, हवा और पानी के कारण भी हम मर और बीमार पड़ ही रहे हैं। प्रश्न यह है कि मिट्टी, हवा और पानी में मिलावट तथा रासायनिक असंतुलन के दोशियों को लेकर हमारी निगाह, कायदे और सजा उतनी सख्त क्यों नहीं है ?

■ अरुण तिवारी

मैगी नूडल्स में सीसा यानी लैड की अधिक मात्रा को लेकर उठा बवाल, बाजार का खेल है या स्थिति सचमुच, इतनी खतरनाक है? इस प्रश्न का उत्तर तो चल रही जांच और बाजार में नूडल्स के नये ब्रांड आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल, मांग हो रही है कि इस जांच का विस्तार सभी प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों को लेकर हो। जांच, कार्रवाई और उसे सार्वजनिक करने की नियमित प्रक्रिया बने। यह सब ठीक है; यह हो। किंतु यहां उठाने लायक व्यापक चित्र भिन्न है।

इधर सख्ती, उधर सुस्ती

मूल चित्र यह है कि सीसे की अधिक मात्रा में उपस्थिति चाहे मैगी नूडल्स में हो अथवा हवा, पानी और मिट्टी में; सेहत के लिए नुकसानदेह तो वह सभी जगह है। जिस तरह किसी खाद्य पदार्थ के दूषित होने के कारण हम बीमार पड़ते अथवा मरते हैं, उसी तरह मिलावटी/असंतुलित रासायनिकी वाली मिट्टी, हवा और पानी के कारण भी हम मर और बीमार पड़ ही रहे हैं। प्रश्न यह है कि मिट्टी, हवा और पानी में मिलावट तथा रासायनिक असंतुलन के दोषियों को लेकर हमारी निगाह, कायदे और सजा उतनी सख्त क्यों नहीं है?

खाद्य पदार्थ की तरह मिट्टी, हवा, पानी का रासायनिक अथवा जैविक असंतुलन बिगाड़ने वालों को लेकर बिना किसी की अनुमति, सीधे–सीधे हत्या अथवा हत्या की कोशिश की धाराओं में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई जा सकती? क्या ऐसी सख्ती के बगैर, पर्यावरण के प्रदूषकों को नियंत्रित करना संभव है? क्या यह सच नहीं कि प्रदूषकों को सजा में ढिलाई भी क्या एक ऐसा कारण नहीं है, जिसकी वजह से हमारे विकासकर्ता, पर्यावरण की परवाह नहीं कर रहे?

कहा जा रहा है कि दिल्ली की हवा में बीजिंग से ज्यादा कचरा है। भारत की नदियों में कचरा है। अब यह कचरा मिट्टी में भी उतर रहा है। भारत, भूजल में आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड तथा भारी धातु वाली अशुद्धियों की तेजी से बढोत्तरी वाला देश बन गया है। विकास को हमारा तौर–तरीका कचरा बढ़ा रहा है और प्राकृतिक संसाधन को बेहिसाब खा रहा है। ..तो हम क्या करें ? क्या आदिम युग का जीवन जीयें? क्या गरीब के गरीब ही बने रहें? आप यह प्रश्न कर सकते हैं। ढांचागत और आर्थिक विकास के पक्षधर भी यही प्रश्न कर रहे हैं।

लक्ष्मण रेखा के प्रश्न

ये सभी प्रश्न इसलिए हैं; ताकि हम अपने भौतिक विकास के नाम पर हो रहे अति दोहन और असंतुलन को समझदारी के साथ लक्ष्मण रेखा में ला सकें। हम समझ सकें कि विकास और पर्यावरण, एक–दूसरे के पूरक होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। यह सच है। यह सच, पर्यावरण और विकास को एक–दूसरे की परवाह करने वाले तंत्र के रूप में चिन्हित करता है। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि पर्यावरण और विकास की चाहत रखने वालों ने आज एक–दूसरे को परस्पर विरोधी मान लिया है। भारत के इंटेलीजेंस ब्यूरो ने ऐसे कई संगठनों को विकास में अवरोध उत्पन्न करने के दोषी के रूप में चिन्हित किया है।

हाल ही में अपने खातों को ठीक–ठाक न रख पाने के कारण विदेशी धन लेने वाले करीब 9000 संगठनों के लाइसेंस रद्द करने की सरकारी कार्रवाई को भी इसी आइने में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, पर्यावरण के मोर्चे पर चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। जिनका जवाब बनने की कोशिश कम, सवाल उठाने की कोशिशें ज्यादा हो रही हैं। ऐसा क्यों? जवाब बनने की कोशिशें भी इलाज के रूप में ही ज्यादा सामने आ रही हैं। बीमारी हो ही न, इसके रोकथाम को प्राथमिकता

बनाने का चलन कम नजर आ रहा है। हम समझ रहे हैं कि विकास के जिस रास्ते पर चलने के कारण पर्यावरणीय संकट गहरा गया है, पर्यावरणीय संकट पलटकर उस विकास को ही बौना बना रहा है। जानते, समझते और झेलते हुए भी हम चेत नहीं रहे। ऐसा क्यों? पर्यावरणीय चुनौतियों के मोर्चे पर समाधान के मूल प्रश्न यही हैं।

संकट में पर्यावास

सब जानते हैं कि बढ़ता तापमान और बढ़ता कचरा, पर्यावरण ही नहीं, विकास के हर पहलू की सबसे बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक आकलन है कि जैसे–जैसे तापमान बढेगा, तो बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ती जाएगी। समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा। नतीजे में कुछ छोटे देश व टापू डूब जाएंगे। समुद्र किनारे की कृषि भूमि कम होगी। लवणता बढ़ेगी। समुद्री किनारों पर पेयजल का संकट गहरायेगा। समुद्री खाद्य उत्पादन के रूप में उपलब्ध जीव कम होंगे। वातावरण में मौजूद जल की मात्रा में परिवर्तन होगा। परिणामस्वरूप, मौसम में और परिवर्तन होंगे। बदलता मौसम तूफान, सूखा और बाढ लायेगा। हेमंत और बसंत ऋतु गायब हो जाएंगी। इससे मध्य एशिया के कुछ इलाकों में खाद्यान्न उत्पादन बढेगा। किंतु दक्षिण एशिया में घटेगा।

नहीं चेते, तो खाद्यान्न के मामले में स्वावलंबी भारत जैसे देश में भी खाद्यान्न आयात की स्थिति बनेगी। पानी का संकट बढ़ेगा। जहां बाढ और सुखाड़ कभी नहीं आते थे, वे नये 'सूखा क्षेत्र' और 'बाढ़ क्षेत्र' के रूप में चिन्हित होंगे।

जाहिर है कि इन सभी कारणों से महंगाई बढेगी। दूसरी ओर मौसमी परिवर्तन के कारण पौधों और जीवों के स्वभाव में परिवर्तन आयेगा। पंछी समय से पूर्व अंडे देने लगेंगे। ठंडी प्रकृति वाले पंछी अपना ठिकाना बदलने को मजबूर होंगे। इससे उनके मूल स्थान पर उनका भोजन रहे जीवों की संख्या एकाएक बढ़ जाएगी। कई प्रजातियां लुप्त हो जायेंगे। मनुष्य भीलू, हैजा, जापानी बुखार जैसी बीमारियों और महामारियों का शिकार बनेगा। ये आकलन, जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतर–सरकारी पैनल के हैं।

जिम्मेदार कौन?

पर्यावरण कार्यकर्ता और अन्य आकलन भी इस सभी के लिए इंसान की

अतिवादी गतिविधियों को जिम्मेदार मानते हैं। तापमान में बढोत्तरी का 90 प्रतिशत जिम्मेदार तो अकेले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ही माना गया है। मूल कारण है, अतिवादी उपभोग। सारी दुनिया, यदि अमेरिकी लोगों जैसी जीवन शैली जीने लग जाये, तो 3.9 अतिरिक्त पृथ्वी के बगैर हमारा गुजारा चलने वाला नहीं। अमेरिका, दुनिया का नबंर एक प्रदूषक है, तो चीन नंबर दो।

चेतावनी साफ है; फिर भी भारत, उपभोगवादी चीन और अमेरिका जैसा बनना चाहता है। क्या यह ठीक है? जवाब के लिए अमेरिका विकास और पर्यावरण के जरिए आइये समझ लें कि विकास, समग्र अच्छा होता या सिर्फ भौतिक और आर्थिक?

अमेरिकी विकास और पर्यावरण

संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया की पांच प्रतिशत आबादी रहती है। किंतु प्रदूषण मे उसकी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। कारण कि वहां 30 करोड़ की आबादी के पास 25 करोड़ कारें हैं। बहुमत के पास पैसा है, इसलिए 'यूज एण्ड थ्रो' की प्रवृत्ति भी है। उपभोग ज्यादा हैं, तो कचरा भी ज्यादा है और संसाधन की खपत भी। एक ओर ताजे पानी का बढ़ता खर्च, घटते जल स्रोत और दूसरी तरफ किसान, उद्योग और शहर के बीच खपत व बंटवारे के बढ़ते विवाद। बड़ी आबादी उपभोग की अति कर रही है, तो करीब एक करोड़ अमेरिकी जीवन की न्यूनतम जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विषमता का यह विष, सामाजिक विन्यास बिगाड़ रहा है। हम इससे सीखकर सतर्क हों या प्रेरित हों? सोचिए!

यह खोना है कि पाना?

आर्थिक विकास की असलियत बताते अन्य आंकड़े यह हैं कि प्रदूषित हवा की वजह से यूरोपीय देशों ने एक ही वर्ष में 1.6 ट्रिलियन डॉलर और 6 लाख जीवन खो दिए। एक अन्य आंकड़ा है कि वर्ष–2013 में प्राकृतिक आपदा की वजह से दुनिया ने 192 बिलियन डॉलर खो दिए। दुखद है कि दुनिया में 7400 लाख लोगों को वह पानी मुहैया नहीं, जिसे किसी भी मुल्क के मानक पीने योग्य मानते हैं। दुनिया में 40 प्रतिशत मौत पानी, मिट्टी और हवा में बढ़ आए प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। हमें होने वाली 80 प्रतिशत बीमारियों की मूल वजह पानी का प्रदूषण, कमी या अधिकता ही बताया जा रहा है।

कहा जा रहा है कि दिल्ली की हवा में बीजिंग से ज्यादा कचरा है। भारत की नदियों में कचरा है। अब यह कचरा मिट्टी में भी उतर रहा है। भारत, भूजल में आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड तथा भारी धातु वाली अशुद्धियों की तेजी से बढोत्तरी वाला देश बन गया है। विकास को हमारा तौर–तरीका कचरा बढ़ा रहा है और प्राकृतिक संसाधन को बेहिसाब खा रहा है।

..तो हम क्या करें ? क्या आदिम युग का जीवन जीयें? क्या गरीब के गरीब ही बने रहें? आप यह प्रश्न कर सकते हैं। ढांचागत और आर्थिक विकास के पक्षधर भी यही प्रश्न कर रहे हैं।

भारत क्या करें?

जवाब है कि भारत सबसे पहले अपने से प्रश्न करें कि यह खोना है कि पाना ? भारत, सभी के शुभ के लिए लाभ कमाने की अपनी महाजनी परंपरा को याद करे। हर समस्या में समाधान स्वतः निहित होता है। इस स्पष्टता के बावजूद हम न तो पानी के उपयोग में अनुशासन तथा पुर्नोपयोग व कचरा प्रबंधन में दक्षता ला पा रहे हैं और नहीं ऊर्जा के। यह कैसे हो? सोचें और करें। नैतिक और कानूनी.. दोनो स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि जो उद्योग जितना पानी खर्च करे, वह उसी क्षेत्र में कम से कम उतने पानी के संचयन का इंतजाम करे। प्राकृतिक संसाधन के दोहन कचरे के निष्पादन, शोधन और पुर्नोपयोग को लेकर उद्योगों को अपनी क्षमता और ईमानदारी, व्यवहार में दिखानी होगी। सरकार को भी चाहिए कि वह पानी–पर्यावरण की चिंता करने वाले कार्यकर्ताओं को विकास विरोधी बताने की बजाय, समझे कि पानी बचेगा, तो ही उद्योग बचेंगे; वरना किया गया निवेश भी जायेगा और भारत का औद्योगिक स्वावलंबन भी।

पर्यावरण को लेकर बढते विवाद, बढ़ती राजनीति, बढ़ता बाजार, बढ़ते बीमार, बढ़ती प्यास और घटती उपलब्धता को देखते हुए यह नकारा नहीं जा सकता कि पर्यावरण, विकास को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता जितनी घटती जायेगी, विकास के सभी पैमाने हासिल करने की चीख–पुकार उतनी बढ़ती जायेगी। अतः प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और शुचिता बढ़ाने की प्राथमिकता है ही।

सोच बदलें

नियमन के मोर्चे पर जरूरत परियोजनाओं से होने वाले मुनाफे में स्थानीय समुदाय की हिस्सेदारी के प्रावधान करने से ज्यादा, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण रोकने की है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत में प्रकृति से साथ रिश्ते की भारतीय संस्कृति का संदर्भ पेश करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का बेलगाम दोहन रोकने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जरूरी है कि यह प्रतिबद्धता, जमीन पर उतरे। बैराज, नदी जोड़, जलमार्ग, जलविद्युत, भूमि विकास, नगर विकास, खनन, उद्योग आदि के बारे में निर्णय लेते वक्त विश्लेषण हो कि इनसे किसे कितना रोजगार मिलेगा, कितना छिनेगा? किसे, कितना मुनाफा होगा और किसका, कितना मुनाफा छिन जायेगा? जीडीपी को आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक मानने से पहले सोचना ही होगा कि जिन वर्षों में भारत में जीडीपी सर्वोच्च रही, उन्ही वर्षों में किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े सर्वोच्च क्यों रहें?

पर्यावरण को लेकर बढते विवाद, बढती राजनीति, बढता बाजार, बढते बीमार, बढती प्यास और घटती उपलब्धता को देखते हुए यह नकारा नहीं जा सकता कि पर्यावरण, विकास को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता जितनी घटती जायेगी, विकास के सभी पैमाने हासिल करने की चीख–पुकार उतनी बढती जायेगी। अतः प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और शुचिता बढाने की प्राथमिकता है ही। विकास, उपभोग और पर्यावरण के बीच संतुलन साधकर ही यह संभव है। संतुलन बिगाड़ने वालों को लक्ष्मण रेखा में लाकर ही हो सकता है। मैगी नूडल्स में सीसे का संदेश यही है और पर्यावरण दिवस का भी। ❑

आज भी बदलने को तैयार नहीं चीन

प्रधानमंत्री मोदी की प्रचारित यात्रा दोनों देशों के उच्चस्तरीय दौरों, समझौतों और संयुक्त बयानों के उपयोग के ख्याल से बहुत ठीक थी। लेकिन भारत–चीन संबंधों का रास्ता अतिश्योक्तिपूर्ण या खोखले समझौतों और घोषणाओं के यादगारी पत्थरों से अटा पड़ा है। नवीनतम मिलन की आभा धुंधली होने और बदले की भावना वाली कठोर सैन्य सच्चाई फिर उभरने में बहुत देर नहीं होने वाली।

■ ब्रह्मा चेलानी

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपनी परियोजनाओं, सीमा विवाद और दक्षिण चीन सागर के बारे में चीन की ओर से दिए गए हाल के बयानों से साफ है कि उसके रवैये में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा एक राजनयिक दांव था। उनका लक्ष्य था– चीन–भारत समीकरण में बुनियादी बदलाव।

प्रधानमंत्री मोदी ने तर्क दिया है कि 21वीं सदी एशिया की है और यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि विश्व की दो–तिहाई आबादी वाले दो देश – 'भारत और चीन' अपने यहां कितनी प्रगति करते हैं और दोनों एक–दूसरे के लिए क्या करते हैं। लेकिन अपनी चुनावी जीत की पहली वर्षगांठ के समय मोदी का यह दौरा इस बात की याद दिलाने के लिए था कि शिखर सम्मेलनों में भारत–चीन सौहार्द वास्तविकता से अधिक दिखावटी है, लेकिन चीन का दौरा करने वाले पहले के भारतीय प्रधानमंत्रियों की तरह मोदी भी खाली हाथ लौटे।

वस्तुतः तड़क–भड़क से भरा और पर्यटन स्थल की सैर वाला यह दौरा उन मुद्दों को हल करने में सफल नहीं रहा जो दोनों देशों के बीच मतभेद का प्रमुख कारण हैं। राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री ली कछियांग के साथ बातचीत में मोदी ने सीमा विवाद को रेखांकित किया। यह दुनिया का सबसे लंबा अनिर्णीत सीमा विवाद है। सन 2006 से चीनी सेना की बढ़ती घुसपैठ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' की अस्पष्टता के कारण संवेदनशील हिमालयी इलाकों पर 'अनिश्चितता की छाया' मंडरा रही है जो चीन ने मनमर्जी से तब खींच ली थी जब उसने 1962 में भारत को पराजित किया था। उन्होंने घोषणा की कि इसीलिए मैंने इसे स्पष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। करीब दो दशकों तक सीमा पर बातचीत के बाद 2002 में चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्टीकरण प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया। उसने हिमालय के दोनों तरफ स्थित मुख्य विवादित क्षेत्रों के नक्शों की अदला–बदली से इंकार कर दिया।

इनमें एक है अक्साई चिन समेत लद्दाख जो स्विट्जरलैंड के आकार का पठारी इलाका है और दूसरा है आस्ट्रिया के आकार का भारत की म्यांमार सीमा से सटा अरुणाचल प्रदेश जिस पर दावा ठोकने में 2006 से वह अधिक सक्रियता दिखा रहा है। वैसे, चीनी सैन्य घुसपैठ 4057 किलोमीटर लंबी हिमालयी सीमा के अधिकांश हिस्से में हो रही है। मोदी का दौरा शी के गृहनगर शियान से शुरू हुआ। यह चीन की चार प्राचीन राजधानियों में एक है। शी ने शियान में मोदी के साथ विधिवत बातचीत की और वहां वाइल्ड गूज पैगोरा देखने गए। मोदी के साथ ली बीजिंग के टेंपल ऑफ हेवन गए। मोदी शी के साथ व्यक्तिगत दोस्ती की बात कहते तो हैं, फिर भी वह किसी मुद्दे पर चीनी पक्ष को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाए।

आदान–प्रदान कूटनीति का पहला

भारत–चीन व्यापार दुनिया का सबसे एकतरफा व्यापार संबंध है। भारत के सबसे बड़े आयात स्रोत चीन से निर्यात आयात की तुलना में पांच गुना ज्यादा है। बीजिंग भारत से मुख्यतः प्राथमिक माल खरीदता है, लेकिन भारत को वर्धित मूल्य वाली चीजें बेचता है। भारत ने अपने बाजार में भर जाने वाले सस्ते चीनी सामानों को रोकने की दिशा में ज्यादा कुछ नहीं किया है। वह भारत की संभावनाओं को कमतर करने के ख्याल से अपने व्यापारिक विस्तार का उपयोग कर रहा है। कम कीमत पर सामान बेचने की अनुमति समेत विकृत व्यापार के जरिये ज्यादा लाभ कमाने के मौके देकर भारत अपने को घेरने की चीनी रणनीति को ही पल्लवित–पोषित कर रहा है।

सिद्धांत होता है, फिर भी छूट भारतीय पक्ष से दी गई। उदाहरण के लिए, भारतीय सुरक्षा तंत्र को दरकिनार कर मोदी ने घोषणा की कि चीनी पर्यटक भारत आने पर इलेक्ट्रानिक वीजा पाने के अधिकारी होंगे। यह अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को नत्थी वीजा जारी किए जाने की चीनी नीति के बावजूद उसे इनाम दिए जाने जैसा कदम है। नत्थी वीजा दिया जाना अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता पर सवालिया निशान है।

प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को चीन के विदेश मंत्री ने 'उपहार' कहा, लेकिन अचानक की गई इस घोषणा से अपने विदेश सचिव भी भौचक रह गए। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही मीडिया से कहा था कि इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। सितंबर में शी के दौरे के समय भी मोदी तिब्बत पर दबाव में आ गए थे। पवित्र कैलास मानसरोवर का दौरा करने वाले भारतीय तीर्थ–यात्रियों के संदर्भ में बीजिंग के संयुक्त बयान में 'चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र' का जिक्र किया गया। छिन्न–भिन्न तिब्बत के लिए 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र' चीन का सरकारी नाम है हालांकि क्षेत्र में कुछ भी स्वायत्त नहीं है। वहां सीधे बीजिंग से शासन चलाया जाता है।

तिब्बत को चीन का हिस्सा बताया जाना 2010 से जारी भारत की उस पुनरीक्षित नीति को नकारना है जिसमें यह बात तय की गई थी कि किसी संयुक्त बयान में तब तक इस तरह का जिक्र नहीं किया जाएगा जब तक चीन भारत के नक्शे को बदरंग करने का क्रम जारी रखता है। इस तरह दबने की जगह बीजिंग का रवैया भारत को समायोजित करने का था।

संयुक्त बयान में प्रोत्साहन के तौर पर कहा गया कि चीन ने परमाणु आपूर्ति संगठन का 'सदस्य बनने की भारत की इच्छाओं पर ध्यान दिया' और वह 'सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में बेहतर भूमिका निभाने की भारत की इच्छाओं को समझता और समर्थन देता है।

चीन एकमात्र प्रमुख देश है जिसने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत के प्रवेश का समर्थन नहीं किया है। दौरे में 24 समझौते हुए, लेकिन इनमें से अधिकांश संकेतात्मक थे। बातचीत हो रही थी, पर एक महत्वपूर्ण समझौता नहीं हो पाया– सीमा के आर–पार वाली नदियों के जल–वैज्ञानिक आंकड़ों को चीन को पूरे साल भेजने का प्रस्ताव।

तिब्बत को चीन का हिस्सा बताया जाना 2010 से जारी भारत की उस पुनरीक्षित नीति को नकारना है जिसमें यह बात तय की गई थी कि किसी संयुक्त बयान में तब तक इस तरह का जिक्र नहीं किया जाएगा जब तक चीन भारत के नक्शे को बदरंग करने का क्रम जारी रखता है। इस तरह दबने की जगह बीजिंग का रवैया भारत को समायोजित करने का था।

अभी ये आंकड़े सिर्फ बारिश के दिनों में दिए जाते हैं। जल भंडार वाले तिब्बत पर चीन का कब्जा है और इसलिए वह जल अधिपति हो गया है। वह किसी पड़ोसी के साथ जल बंटवारा समझौता करने से इंकार करता है। इस समझौते का रुकना नदी के बहाव पर पूरे साल के आंकड़े के भी आदान–प्रदान पर चीन की अरुचि का संकेत है।

शंघाई में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ मोदी की बैठक के दौरान 22 अरब डॉलर के करार की काफी चर्चा हुई। इनमें से कई करार चीनी सामान खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों को धन देने के लिए चीनी सरकार के बैंकों वाले हैं। चीन के साथ भारत के पहले से ही भारी व्यापार घाटे को ये और बढ़ाएंगे ही। भारत में चीनी निवेश को बढ़ाने में इनकी थोड़ी–सी ही भूमिका होगी। यह भारत के साथ चीन के वार्षिक व्यापार अधिशेष का कुल मिलाकर एक प्रतिशत है।

भारत–चीन व्यापार दुनिया का सबसे एकतरफा व्यापार संबंध है। भारत के सबसे बड़े आयात स्रोत चीन से निर्यात आयात की तुलना में पांच गुना ज्यादा है। बीजिंग भारत से मुख्यतः प्राथमिक माल खरीदता है, लेकिन भारत को वर्धित मूल्य वाली चीजें बेचता है। भारत ने अपने बाजार में भर जाने वाले सस्ते चीनी सामानों को रोकने की दिशा में ज्यादा कुछ नहीं किया है। वह भारत की संभावनाओं को कमतर करने के ख्याल से अपने व्यापारिक विस्तार का उपयोग कर रहा है। कम कीमत पर सामान बेचने की अनुमति समेत विकृत व्यापार के जरिये ज्यादा लाभ कमाने के मौके देकर भारत अपने को घेरने की चीनी रणनीति को ही पल्लवित–पोषित कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की प्रचारित यात्रा दोनों देशों के उच्चस्तरीय दौरों, समझौतों और संयुक्त बयानों के उपयोग के ख्याल से बहुत ठीक थी। लेकिन भारत–चीन संबंधों का रास्ता अतिश्योक्तिपूर्ण या खोखले समझौतों और घोषणाओं के यादगारी पत्थरों से अटा पड़ा है। नवीनतम मिलन की आभा धुंधली होने और बदले की भावना वाली कठोर सैन्य सच्चाई फिर उभरने में बहुत देर नहीं होने वाली।❑

पूर्वोत्तर में आतंक की अनदेखी का अंजाम

एक अमेरिकी खुफिया रपट बताती है कि गोल्डन ट्राइंगल से म्यामार के रास्ते हथियारों के बदले नशीली दवाओं के व्यापार पर भारत सरकार न जाने क्यों कड़ी कार्रवाई करने से बचती है। यह वही जगह है जहां से श्रीलंका में खून–खराबे के दिनों में लिट्टे तक हथियारों की खेप पहुंचती थी। जिस तरह से उत्तर–पूर्वी राज्यों के उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों तथा उसके लिए जरूरी गोला–बारूद से लैस रहते हैं, उससे यह तो साफ है कि कोई तो है जो दक्षिण–पूर्व एशिया में अवैध खतरनाक हथियारों की खपत बनाए रखे हुए है।

■ पंकज चतुर्वेदी

बीते चार जून को मणिपुर में सेना पर हुए हमले से पहले दो अप्रैल और छह फरवरी को अरुणाचल में सेना पर हमले हो चुके है। इन सभी हमलों का शक नगालैंड के पृथकतावादी संगठन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड के खपलांग गुट पर है। मुल्क में जब कभी आतंकवाद से निबटने का मुद्दा सामने आता है तो क्या आम लोग और क्या नेता और अफसरान, सभी कश्मीर पर आंसू बहाने लगते हैं।

लंबे समय से यह बात नजरअंदाज की जाती रही है कि हमारे *'सेवन सिस्टर्स'* राज्यों में अलगाववाद और आतंकवाद कश्मीर से कहीं ज्यादा है और उससे सटी सीमा के देशों– चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश ही नहीं थाईलैंड, जापान तक इन संगठनों के आका बैठकर अपनी समानांतर हुकूमत चला रहे हैं। अभी मणिपुर की सरकार म्यांमार से सहयोग मांग रही है।

उत्तर–पूर्वी राज्यों मणिपुर, असम, नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कोई पच्चीस उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। यहां बीते बारह सालों के दौरान कोई बीस हजार लोग मारे गए जिनमें चालीस फीसद सुरक्षाकर्मी हैं। जब किसी राज्य में कुछ महीने शांति रहती है तो माना जाता है कि सरकार ने उग्रवादी संगठनों को मनमाने तरीके से उगाही की छूट दे दी है।

हालांकि पूर्वोत्तर में उग्रवाद का संबंध चीन के कम्यूनिस्ट आंदोलन से जोड़ा जाता है, लेकिन यह भी गौरतलब है कि पूरे क्षेत्र में कभी चर्च या मिशिनरी के किसी भी दल, संपत्ति या गतिविधि पर उग्रवादी मार नहीं पड़ी। असम में उल्फा, एनडीबीएफ, केएलएनएलएफ और यूपीएसडी के लड़ाकों का बोलबाला है। अकेले उल्फा के पास अभी भी 1600 लड़ाके हैं जिनके पास 200 एके राइफलें, 20 आरपीजी और 400 दीगर किस्म के असलहा हैं। राजन दायमेरी के नेतृत्व वाले एनडीबीएफ के आतंकवादियों की संख्या 600 है जो 50 एके तथा 100 अन्य किस्म की राइफलों से लैस हैं।

बीते साल असम में बड़े नरसंहार करने वाले एनडीबीएफ के सांगबीजित गुट का मुखिया आईके संगबीजित म्यांमार में रह कर अपने व्यापार करता है। आश्चर्यजनक है कि बोडो के नाम पर खून–खराबा करने वाला यह अपराधी खुद बोडो नहीं है।

नगालैंड में पिछले एक दशक के दौरान अलग देश की मांग के नाम पर डेढ़ हजार लोग मारे जा चुके हैं। वहां एनएससीएन के दो घटक– आईएम और खपलांग– बाकायदा सरकार के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर जनता से चौथ

वसूलते हैं। इनके आका विदेश में रहकर भारत सरकार से संपर्क में रहते हैं और इनके गुर्गे को अत्याधुनिक प्रतिबंधित हथियार लेकर सरेआम घूमने की छूट होती है। यहां तक कि राज्य की सरकार का बनना और गिरना भी इन्हीं उग्रवादियों के हाथों में होता है। यह बात हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में सामने आ चुकी है।

कांग्रेस बहुत प्रचार कर रही थी कि आईएम गुट के साथ जल्दी ही शांति समझौता हो जाएगा, लेकिन सत्ताधारी नगा नेशनल फ्रंट आईएम गुट को यह विास दिलाने में सफल रहा कि उसकी सरकार फिर से बनने पर उनके लिए राहत होगी। बांग्लादेश की सीमा से सटे त्रिपुरा में एनएलएफटी और एटीटीएफ की तूती बोलती है। इन दोनों संगठनों के मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और छिपने के ठिकाने बांग्लादेश में हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इन संगठनों को उकसाने व मदद करने का काम हुजी व हरकत उल अंसार जैसे संगठन करते हैं।

छोटे राज्य मणिपुर में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह पीएलए, यूएनएलएफ और पीआरइपीएके जैसे संगठनों का गुलाम हैं। यहां सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा आतंकवादियों को देना ही होता है। बाहरी लोगों की यहां खैर नहीं है। केवाईकेएल यानि कांग्लेई यावोल कन्न ललुप संगठन भी राज्य के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय है। बीते दस सालों के दौरान यहां पांच हजार से ज्यादा लोग अलगाववाद के शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा नगा–कुकी तथा कुकी–जोमियो संघर्ष में सात सौ से ज्यादा जानें गई हैं।

यहां सबसे ज्यादा ताकतवर संगठन यूनाइटेड नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट है जिसके पास 1500 लोग हैं। दूसरे सबसे खतरनाक संगठन पीपुल लिबरेशन आर्मी के 400 सदस्य हैं। ये सभी संगठन अत्याधुनिक हथियारों व संचार उपकरणों से लैस हैं। मेघालय में एएनयूसी और एचएनएलएल नामक संगठन अलगाववाद के झंडाबरदार हैं, वहीं मिजोरम में एनपीसी और बीएनएलएफ राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग हैं। इसके अलावा असम को आधार बनाकर कई गुमनाम संगठन भी अलगाववाद की रट लगाए हैं। इनमें से कई सीधे–सीधे पाकिस्तानी आईएसआई की पैदाइश हैं।

असम में छोटे–बड़े 36 आतंकवादी संगठनों का अस्तित्व सरकारी रिकार्ड स्वीकार करता है। मणिपुर में 39, मेघालय में पांच, मिजोरम में दो, नगालैंड में तीन, त्रिपुरा में 30 और अरुणाचल प्रदेश में महज एक अलगाववादी संगठन है। इनमें से अधिकांश को पाकिस्तान और बांग्लादेश में बने बेस कैंपों से खाद–पानी मिलता है। उत्तर–पूर्वी राज्यों में बहुत से संगठन सक्रिय हैं और वहां उग्रवाद कश्मीर से कहीं ज्यादा है। इसके बावजूद श्रीनगर में हथगोला फटने की खबर टीवी व अखबारों पर छायी होती है, जबकि उत्तर–पूर्व के भीषण नरसंहार भी बमुश्किल जगह पाते हैं।

यहां यह भी जानना जरूरी है कि बांग्लादेश से लगी सीमा के 4096 किलोमीटर पर भारत सरकार पहले ही कंटीले तारों की बाड़ लगा चुकी हैं, जबकि म्यांमार से सटी सीमा पर 1643 किलोमीटर पर गहरी खाई हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल आदि के हजारों जवान भी लगे हैं।

साफ जाहिर है कि इन राज्यों में आतंकवादियों को सीमापार आने के लिए आंख चुराकर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे कई बार फर्जी पासपोर्ट या अन्य जरियों से भीतर आते–जाते रहते हैं। अनूप चेतिया और परेश बरुआ के मामले में सामने आ चुका है कि इन लोगों ने बैंकाक और ढाका में पांच सितारा होटल से लेकर जहाज कंपनी तक के व्यापार विधिवत खोल रखे हैं। यह तय भारत सरकार की खुफिया एजेंसियों को कई साल पहले पता था कि बांग्लादेश का काक्स बाजार बंदरगाह हथियारों के सौदागरों का प्रमुख अड्डा बना हुआ है और वहां पहुंचने के लिए अंडमान सागर का इस्तेमाल किया जाता है।

एक अमेरिकी खुफिया रपट बताती है कि गोल्डन ट्राइंगल से म्यामार के रास्ते हथियारों के बदले नशीली दवाओं के व्यापार पर भारत सरकार न जाने क्यों कड़ी कार्रवाई करने से बचती है। यह वही जगह है जहां से श्रीलंका में खून–खराबे के दिनों में लिट्टे तक हथियारों की खेप पहुंचती थी। जिस तरह से उत्तर–पूर्वी राज्यों के उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों तथा उसके लिए जरूरी गोला–बारूद से लैस रहते हैं, उससे यह तो साफ है कि कोई तो है जो दक्षिण–पूर्व एशिया में अवैध खतरनाक हथियारों की खपत बनाए रखे हुए है। बंदूक के बल पर लोकतंत्र को गुलाम बनाने वालों को हथियार की सप्लाई म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, बांग्लादेश से हो रही है। मणिपुर को, जहां सबसे ज्यादा उग्रवाद है, नशे की लत से बेहाल और उससे उपजे एड्स के लिए देश का सबसे खतरनाक राज्य कहा जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि यहां नारकोटिक्स व्यापार के बदले हथियार की खेप पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। ❑

चुनावी राजनीति से ऊपर सामाजिक बदलाव

जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के प्रयास अलगाव में न हों। उन्हें एक अधिक व्यापक सार्थक सामाजिक बदलाव के हिस्से के रूप में समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। इस तरह उनका वैचारिक आधार मजबूत बना रहेगा। इस तरह का कोई राजनीतिक दल ही सही अर्थों में वैकल्पिक राजनीति कर सकेगा। उसके सामने बहुत स्पष्ट नीतियां होंगी, जिन्हें अपना कर समाज में व्याप्त दुख–दर्द व उसके कारणों को टिकाऊ तौर पर कम किया जा सकता है व साथ में भविष्य की अधिक गंभीर समस्याओं की संभावनाओं को भी कम किया जा सकता है।

■ भारत डोगरा

यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती ही है कि समाज में तरह–तरह के रचनात्मक कार्य व समाज–सुधार के प्रयासों के लिए जगह है, कमजोर वर्ग के संगठनों व रचनात्मक कार्य के संस्थानों के आगे आने के लिए स्थान है। लेकिन इसके बावजूद यह प्रयास बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। छिटपुट स्तर पर कई अच्छे प्रयास हो रहे हैं। कुछ पंचायतों, ब्लाक या जिला स्तर पर कुछ संस्थाओं ने बहुत राहत पंहुचाई है। कुछ निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने उत्साहवर्धक कार्य किया है। लेकिन ये प्रयास कितने भी सराहनीय रहे हों, इनमें अभी समाज में किसी ऐसे व्यापक व टिकाऊ बदलाव की आहट नहीं मिल रही है जो वास्तविक जरूरतों व चुनौतियों की दृष्टि से बहुत सार्थक व समग्र हो। इस तरह के किसी व्यापक सामाजिक बदलाव के अभाव में बदलाव की बात मुख्य रूप से चुनावी राजनीति के इर्द–गिर्द सिमट कर रह गई है।

हाल के समय में अन्ना आंदोलन के रूप में ऐसा कुछ माहौल चंद दिनों के लिए जरूर बनता नजर आया था पर इसका अपना आधार कमजोर था क्योंकि सारा जोर एक लोकपाल की मांग पर ही केंद्रित हो गया था जो आधे–अधूरे सामाजिक बदलाव का प्रतीक था। बाद में इन्हीं में से अनेक आंदोलनकारियों ने स्वयं ही इस मांग को अधिक महत्व नहीं दिया। आज की अनेक बड़ी समस्याओं के मूल में यही वजह है कि समाज में ऐसा कोई व्यापक व सार्थक बदलाव का जन–अभियान या आंदोलन नहीं है जो लोगों को प्रेरित करे और एक उम्मीद दे सके।

जाहिर है, यदि समाज में व्यापक चिंतन–मंथन न हो तो इसका दलगत राजनीति की गुणात्मकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है। विडम्बना यह है कि राजनीतिक दलों की गतिविधियां सत्ता केंद्रित होती गई हैं। उनका समाज के सार्थक बदलाव से सरोकार कम होता गया है। आज आम लोगों की बातचीत में बदलाव की चर्चा मुख्य रूप से चुनावी राजनीति में सत्ता–बदलाव के संदर्भ में ही होती है। इस बारे में चर्चा बहुत कम होती है कि किसी व्यापक सामाजिक आंदोलन या अभियान की नई गतिविधियां क्या हैं या उद्देश्य क्या हैं।

हाल के समय में अन्ना आंदोलन के रूप में ऐसा कुछ माहौल चंद दिनों के लिए जरूर बनता नजर आया था पर इसका अपना आधार कमजोर था क्योंकि सारा जोर एक लोकपाल की मांग पर ही केंद्रित हो गया था जो आधे–अधूरे सामाजिक बदलाव का प्रतीक था। बाद में इन्हीं में से अनेक आंदोलनकारियों ने स्वयं ही इस मांग को अधिक महत्व नहीं दिया। आज की अनेक बड़ी समस्याओं के मूल में यही वजह है कि समाज में ऐसा कोई व्यापक व सार्थक बदलाव का जन–अभियान या आंदोलन नहीं है जो लोगों को प्रेरित करे और एक उम्मीद दे सके।

सार्थक सामाजिक बदलाव के बारे के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष के बारे में स्पष्ट सोच बनाना और इसका प्रसार करना मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रगति के तमाम दावों व बाहरी चमक–दमक के बावजूद समाज में दुख–दर्द कम नहीं हुआ है। कुछ सीमित संदर्भ में तरक्की नजर आती है तो इससे अधिक व्यापक संदभरे में दुख–दर्द बढ़े हुए नजर आते हैं। इसमें भी बड़ी बात है कि बढ़ते पर्यावरणीय विनाश, जल, जंगल, जमीन जैसे आधारभूत संसाधनों की गंभीर क्षति के कारण भविष्य में समस्याएं उत्तरोत्तर बढ़ते जाने की आशंका है। टूटते–छीजते सामाजिक ताने–बाने को देखें या हिंसा व महाविनाशक हथियारों में अपार वृद्धि, तेजी से विलुप्त होती

प्रजातियां या जलवायु बदलाव, विज्ञान के युग में भी बढ़ता कट्टरता व अंधविास या तकनीकी का दुरुपयोग, सभी बिंदुओं पर वर्तमान स्थिति चिंताजनक है और इनके भविष्य में और चिंताजनक बनने की आशंकाएं हैं।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि समाज में बड़े स्तर पर व्याप्त दुख–दर्द व उसके कारणों को कम करने के लिए व भविष्य में इससे भी गंभीर समस्याओं की संभावनाओं को दूर करने के लिए बुनियादी बदलाव की जरूरत है। इस बात को इस रूप में कहा जा सकता है कि समाज में क्रांति की जरूरत है, पर साथ में यह स्पष्ट करना होगा कि इसका अर्थ बम व बंदूक की क्रांति से नहीं है। इसका अर्थ सुलझे–विचारों व उनसे जुड़े कार्य की क्रान्ति से है जिनके आधार पर अधिकांश लोग समाज के सबसे जरूरी सरोकारों से जुड़ सकते हैं।

ये कार्य निश्चय ही समता, पर्यावरण रक्षा, शान्ति, भाईचारा व जीवों की रक्षा से जुड़े हैं पर इनको मौजूदा समय की जरूरतों के संदर्भ में स्थापित करने और उनमें आपसी सामंजस्य की चुनौती सामने है। जिस रूप में पर्यावरण की रक्षा को आज से 50 वर्ष पहले समझा जाता रहा है, वह आज की स्थितियों से बहुत अलग है। इसी तरह विश्व शान्ति की जो समझ 50 वर्ष पहले की थी, वह आज से काफी अलग है।

अतः नई स्थितियों के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों, कार्यक्रमों व उनके अंतर्संबंधों को विस्तार से निर्धारित करना बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। व्यापक सामाजिक बदलाव का यह कार्यक्रम निश्चय ही ऐसा होना चाहिए जिसमें विभिन्न तरह के जरूरतमंद लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान नजर आए, पर विचार व प्रतिबद्धता में इससे एक कदम आगे जाने की जरूरत है। केवल अपनी समस्याओं से आगे बढ़कर दूसरों की समस्याओं, अपने से अधिक जरूरतमंदों की समस्याओं व पूरी धरती के सब जीवों के दुख–दर्द के संदर्भ में एक व्यापक प्रतिबद्धता स्थापित करने की जरूरत है।

ऐसा होने पर सोचने–समझने में, विभिन्न मुद्दों के प्रति नजरिए में बड़ा बदलाव आ जाता है व समाज में ऐसा बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इस तरह के व्यापक सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया समाज में चलती रहनी चाहिए। वह चाहे मुख्य रूप से एक अभियान के रूप में चले या थोड़े–बहुत बदलाव के साथ कई अभियानों में, पर यह प्रक्रिया व्यापक स्तर पर चलती रहनी चाहिए।

नई स्थितियों के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों, कार्यक्रमों व उनके अंतर्संबंधों को विस्तार से निर्धारित करना बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। व्यापक सामाजिक बदलाव का यह कार्यक्रम निश्चय ही ऐसा होना चाहिए जिसमें विभिन्न तरह के जरूरतमंद लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान नजर आए, पर विचार व प्रतिबद्धता में इससे एक कदम आगे जाने की जरूरत है।

इस व्यापक चिंतन–मंथन से ही समाज को कई स्तरों पर सही राह मिलेगी व तरह–तरह के भटकाव की संभावना कम होगी। सत्ता की राजनीति ऐसे किसी व्यापक सामाजिक बदलाव से बड़ी नहीं हो सकती है। उसको व्यापक सामाजिक बदलाव के एक हिस्से या एक पक्ष के रूप में ही जगह मिलनी चाहिए।

हाल के समय के तथाकथित वैकल्पिक राजनीति के प्रयास इस कारण आधे–अधूरे रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसे किसी व्यापक सामाजिक बदलाव की छाया नहीं मिली है, सहारा नहीं मिला है। इस कारण यह छिटपुट प्रयास बहुत कम समय में ही तरह–तरह के भटकाव का शिकार होते चले गए।

दूसरी ओर यह कहना भी अनुचित है कि व्यापक सार्थक बदलाव का अभियान अपने आप में पूर्ण है। उसे सत्ता प्राप्त करने की राजनीति से जुड़ना ही नहीं चाहिए। इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सत्ता प्राप्त होने से कई सार्थक कायरे व विचारों के तेजी से प्रसार की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। इसकी जरूरत भी है। कई अनुचित प्रवृत्तियों को रोकना भी जरूरी है। इस कार्य में भी सत्ता प्राप्त करने से संभावनाएं बढ़ती हैं।

अतः यह कहना कि व्यक्ति या संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की ओर से पूरी तरह उदासीन हो जाना चाहिए, भी उचित नहीं कहा जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के प्रयास अलगाव में न हों। उन्हें एक अधिक व्यापक सार्थक सामाजिक बदलाव के हिस्से के रूप में समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। इस तरह उनका वैचारिक आधार मजबूत बना रहेगा। इस तरह का कोई राजनीतिक दल ही सही अर्थों में वैकल्पिक राजनीति कर सकेगा। उसके सामने बहुत स्पष्ट नीतियां होंगी, जिन्हें अपना कर समाज में व्याप्त दुख–दर्द व उसके कारणों को टिकाऊ तौर पर कम किया जा सकता है व साथ में भविष्य की अधिक गंभीर समस्याओं की संभावनाओं को भी कम किया जा सकता है। ❑

समाचार परिक्रमा

2025 तक 21 खरब डालर हो जाएगा खुदरा कारोबार

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और वजीर एडवाइजर्स की ''द इंडियन रिटेल मेडले' नाम से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में खुदरा क्षेत्र का कारोबार वर्तमान के 550 अरब डालर से बढ़कर वर्ष 2020 में 12 खरब डालर और 2025 में 21 खरब डालर का हो जाएगा जिससे अगले दशक में रोजगार के एक करोड़ से अधिक अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस अवधि में संगठित खुदरा क्षेत्र सात गुना और आनलाइन खुदरा कारोबार 26 गुना बढ़ जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार देश में तकनीकी युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है जिससे आनलाइन कारोबार का इजाफा हो रहा है। एक सर्वे के अनुसार अभी देश में करीब 50 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ष 2018 तक यह संख्या बढ़कर 55 करोड़ तक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी और बदलती जीवनशैली से भी आनलाइन खुदरा कारोबार को प्रोत्साहन मिला है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्ष 2018 तक ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़कर 21 करोड़ हो जाएगी जिससे असंगठित खुदरा कारोबार को भी आनलाइन प्लेटफार्म का लाभ मिल सकेगा। सीआईआई रिटेल के अध्यक्ष और लिबर्टी समूह के प्रवर्तक श्री आदेश गुप्ता ने कहा, ''अभी हमारा देश सबसे तेजी से विकास कर रहा है और यह मेक इन इंडिया फार रिटेल इन इंडिया अभियान के लिए सही समय है। हम भारत में खुदरा कारोबार के लिए भारत में ही उत्पादन करेंगे। ❑

बीते एक साल में देश की आर्थिक स्थिति में हुआ है सुधार

उद्योग जगत ने नरेंद्र मोदी सरकार को पहले साल के प्रदर्शन के लिए 10 में से सात नंबर दिए हैं। उद्योग मंडल एसोचैम का कहना है कि कर मुद्दों को सुलझाने का काम अभी भी कुछ बाकी रह गया है जबकि कारोबार में सुगमता को लेकर काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। एसोचैम ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान मुद्रास्फीति में कमी, मुद्रा में स्थिरता व आकर्षक वित्तीय बाजारों की वजह से देश की वृहद आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। एसोचैम के अनुसार ''हालांकि, राजग सरकार को कराधान के मुद्दों पर अभी कुछ दूरी तय करनी है। ❑

अमरीका में चार बड़े बैंकों पर ढाई अरब डालर का जुर्माना

बीते दिनों अमरीका में चार बड़े बैंकों पर 2007 में नियंत्रण मुद्रा बाजार में आपराधिक तरीके से गड़बड़ी करने के मामले में 2.5 अरब डालर का जुर्माना लगाया गया है। ये बैंक हैं जेपी मॉर्गन चेज, सिटीग्रुप, बार्कले और द रायल बैंक आफ स्काटलैंड है। इन बैंकों को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। बैंकों व अमेरिका न्यायिक विभाग के बीच इस मामले के निपटान की घोषणा की गई। इसमें कहा गया है कि दुनिया के बड़े मुद्रा बाजार में अमेरिकी डालर व यूरो के दरों में गड़बड़ी करने के लिए इन बैंकों ने एक–दूसरे के साथ मिलकर साजिश की। बैंकों ने यह आपराधिक व्यवहार दिसम्बर, 2007 से जनवरी, 2013 के दौरान किया। ❑

नियोक्ताओं को नहीं मिल रहे कुशल कर्मचारी

आज देश में कौशल विकास के अभाव में 58 प्रतिशत नियोक्ताओं को जारी वर्ष की पहली तिमाही में नौकरी के लिए कुशल कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। 'मैनपावर ग्रुप के 10वें वार्षिक टैलेंट शार्टेज' द्वारा कराए गए सर्वे में यह जानकारी दी गई। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि नियंत्रण स्तर पर 38 प्रतिशत नियोक्ताओं को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है। शोध सलाह एजेंसी मैनपावर ग्रुप के 42 देशों में किए गए सर्वेक्षण में 41,748 नियोक्ताओं की राय में यह बात सामने आई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इस स्थिति में पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आया है। वर्ष 2014 में 64 प्रतिशत कंपनियों को कुशल कर्मचारी बहाल कर पाने में दिक्कत आई थी। मैन पावर ग्रुप इंडिया के प्रबंध निदेशक एजी राव के अनुसार आज देश में 'आईटी और अकाउंटिंग क्षेत्र में पेशेवरों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तकनीक के उन्नयन और बेहतर वित्तीय पहुंच से आने वाले महीनों में इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में तेजी आ सकती है।'

रिपोर्ट के अनुसार 13 प्रतिशत नियोक्ताओं का मानना है कि गैर कुशल पेशेवरों के कारण उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाने में कठिनाई आती है जिससे उनकी नकारात्मक छवि बनती है। नियंत्रण स्तर पर कुशल कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी जापान (83%) है जबकि इसके बाद पेरू (68%), हांगकांग (65%), ब्राजील (61%), रोमानिया (61%) और यूनान (59%) और भारत (58%) का स्थान है। ❑

मुनाफा बढ़ाकर दिखाती हैं अधिकतर कंपनियां

नियंत्रण लेखा फर्म ईवाई द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक, बड़ी संख्या में कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ा–चढ़ाकर दिखाती हैं और वे ऊंची वृद्धि हासिल करने के लिए भ्रष्ट क्रियाकलापों में लिप्त हैं।

सर्वेक्षण के मुताबिक, प्रतिक्रिया देने वाले 80 प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि कारोबार में घूसखोरी और भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर चलता है। पूर्व में अर्न्स्ट एंड यंग के नाम से जानी जाने वाली ईवाई ने पाया कि वित्तीय नतीजों में छेड़छाड़ की जाती है क्योंकि 40 प्रतिशत लोगों का मानना है कि बाजार में कंपनियां अक्सर वित्तीय निष्पादन को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाती हैं।

सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि ''59 प्रतिशत लोगों का मत है कि कंपनियां अक्सर अपने वित्तीय निष्पादन को उसके बढ़ा चढा कर दिखाती हैं।'

सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि नैतिक कारोबारी व्यवस्था को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इसकी स्वीकार्यता धीरे–धीरे बढ़ती दिख रही है, भले ही इसके स्थापित होने में समय कुछ लग सकता है लेकिन यह स्थापित होगी।' ❑

भारत में आय विषमता सबसे कम

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के उभरते देशों में भारत में आय असामनता सबसे कम है लेकिन अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले यह काफी अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुकाबले जिन देशों में आय विषमता अधिक है उनमें रूस, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच इन देशों में आय असमानता सर्वाधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन दशकों में अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में धनी–गरीब के बीच अंतर बढ़कर उच्च स्तर पर पहुंच गया जबकि कई उभरते देशों में यह लगातार ऊंचा बना हुआ है। विकसित और उभरते देशों में आय विषमता सर्वाधिक दक्षिण अफ्रीका में तथा डेनमार्क में सबसे कम है। नौ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत में आय विषमता सबसे कम है। उसके बाद रूस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, चीन, लातविया, ब्राजील, कोलंबिया और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। ❑

महंगाई के चलते बढ़ रहा 'रेडी टू ईट' भोजन का चलन

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचौम) द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया कि देश में सब्जियों के ऊंचे दाम के चलते बाजार से बना हुआ भोजन खरीद रहा आम आदमी। फल, सब्जी और दाल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोग घरेलू खर्च में कटौती के लिए बाजार में बिकने वाले बने बनाए खाद्य पदार्थो (रेडी टू ईट) भोजन का सहारा लेने लगे हैं। सर्वेक्षण में बताया गया कि आज महानगरों और बड़े शहरों में ज्यादा से ज्यादा लोग घर में खाना बनाने की बजाए बाजार में बिकने वाले बने बनाए और ''रेडी टू ईट' खाद्य पदार्थो का सहारा ले रहे हैं। ❑

देश में कारोबारियों का भरोसा टूटा रहा है

डायचे बोर्स की रिपोर्ट के अनुसार देश का मौजूदा कारोबारी माहौल व भविष्य को लेकर उम्मीदें वापस गिरकर नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले के स्तर पर आ गई है। एमएनआई इंडिया कारोबारी धारणा संकेतक मई में ढाई प्रतिशत घटकर 62.3 पर आ गया, जो अप्रैल मे 63.9 अंक पर था। यह बंबई शेयर बाजार की सूचीबद्ध कंपनियों में मौजूदा धारणा के बारे में संकेत देता है। एमएनआई इंडिकेटर्स के मुख्य अर्थशास्त्री फिलिप यूग्लो ने कहा, ''मई रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि कारोबारी गतिविधियों में गिरावट का रुख है। रिपोर्ट में के अनुसार – मई में औद्योगिक उत्पादन घटकर दो साल के निचले स्तर के करीब आ गया। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी ''मेक इन इंडिया' अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पाया है।' ❑

विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कई सप्ताहों की तेजी के बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार बीते 22 मई को समाप्त सप्ताह में 2.319 अरब डालर की भारी गिरावट के साथ 351.557 अरब डालर रह गया। इस गिरावट का कारण मुख्य मुद्रा आस्तियों में भारी गिरावट का आना है। इससे पूर्व सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.745 अरब डालर बढ़कर 353.876 अरब डालर की रिकार्ड ऊंचाई को छू गया था। ❑

1000 रुपए का नोट छपेगा देसी कागज पर

नोटों की छपाई के लिए देसी कागज की पहली खेप तैयार हो गई है। वित्त मंत्रालय ने के अनुसार पहले खेप पर 1000 रुपए के नोटों की छपाई होगी। इसके अतिरिक्त वित्तमंत्री अरुण जेटली होशंगाबाद में नोटों के लिए देसी कागज बनाने वाले छह हजार टन क्षमता वाले ''न्यू बैंक नोट पेपर लाइन' का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। वर्तमान में नोटों की छपाई के लिए कागज आयात किया जाता है जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाली स्याही देश में ही बनती है। वित्त वर्ष 2013–14 में नोटों के लिए कागज आयात पर 1688.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2011–12 और 2012–13 में यह राशि क्रमशः 1090.36 करोड़ रुपए तथा 13332.84 करोड़ रुपए रही थी। ❑

सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनी रिलायंस

रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी हो गई है। वित्त वर्ष 2014–15 में कंपनी ने 23,566 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया। उसने इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को पीछे छोड़ा है। बंबई शेयर बाजार के पास उपलब्ध सूचीबद्ध कंपनियों के आमदनी के आंकड़ों के अनुसार, ओएनजीसी ने 2014–15 में 18,334 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया। वह इस सूची में फिसलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के बाद तीसरे स्थान पर आ गई है। ❑

आपदा प्रबंधन के लिए कर्ज देगा विश्व बैंक

विश्व बैंक देश के तटीय राज्यों में आपदा प्रबंधन और तमिलनाडु में सड़क परियोजना के लिए 38 अरब 81 करोड़ 59 लाख रुपए का ऋण देगा। विश्व बैंक ने बीते दिनों को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन के दूसरे चरण के लिए 60.84 करोड़ डालर के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस राशि का इस्तेमाल गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों के लिए किया जाएगा। इसके तहत राज्यों की आपदाओं के लिए तैयारी और आपदा के समय कार्रवाई को बेहतर बनाया जाएगा। ❑

विश्व की शीर्ष 60 दूरसंचार कंपनियों में तीन भारतीय कंपनी

दुनिया की 60 सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों की फोर्ब्स की सूची में तीन भारतीय कंपनियों भारती एयरटेल, आइडिया सेल्युलर तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को जगह मिली है। फोर्ब्स की सूची में भारती एयरटेल को सूची में 28 वीं जगह दी गई है। उसकी बिक्री 15 अरब डालर, मुनाफा 80.1 करोड़ डालर, संपत्ति 30.8 अरब डालर तथा बाजार मूल्यांकन 25.8 अरब डालर है। दूसरी सबसे बड़ी भारतीय दूरसंचार कंपनी आइडिया है जिसे ओवर ऑल सूची में 50वें स्थान पर रखा गया है। तीसरी भारतीय कंपनी एमटीएनएल को 56वां स्थान दिया गया है। ❑

भारत से चीन को निर्यात 14% की दर से बढ़ेगा

भारत से चीन का निर्यात 2020–30 के दशक में करीब 14 प्रतिशत सालाना की गति से बढ़ने की उम्मीद है जो किसी भी अन्य देश को निर्यात के मुकाबले अधिक होगा। यह बात एचएसबीसी व्यापार अनुमान रिपोर्ट में बताई गई।

रपट में कहा गया कि सिर्फ इतना ही नहीं उक्त अवधि में ब्राजील समेत नए बाजारों में निर्यात भी 10 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ेगा। एचएसबीसी की रपट में कहा गया, ''निकट भविष्य में भारत का परिदृश्य सकारात्मक है और अन्य देशों (उपभरते और विकसित दोनों किस्म के बाजारों) के मुकाबले अपेक्षाकृत श्रम लागत कम रहने के कारण भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी रहेगा।'❑

देश में रहेगा कमजोर मानसून

देश आज कृषि संकट और किसानों की आत्महत्या से जूझ रहे रहा है और अब बुरी खबर यह है कि इस वर्ष मानसून के कमजोर रहने की आशंका बताई गई है जिससे देश में सूखा पड़ सकता है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं भूविज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने बीते दिनों कहा, कि ''मुझे भारी दिल से कहना पड़ रहा है कि हमारे संशोधित अनुमान के मुताबिक देश में 88 प्रतिशत बारिश होगी जो चार फीसद ज्यादा या कम भी रह सकती है।'

मौसम विभाग ने अनुमान को संशोधित कर 93 से 88 फीसद दीर्घावधि औसत किया है जिसमें देश के उत्तर–पश्चिम हिस्से के सबसे ज्यादा प्रभावित रहने की आशंका है। ❑

190 देशों में मनाया जाएगा योग दिवस

21 जून को 190 देशों के 250 शहरों में योग दिवस एक साथ मनाया जाएगा। ब्रिटेन, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस सहित पूरे यूरोप में योग दिवस जोर–शोर से मनाने की तैयारियां चल रही है। भारतीय ऋषियों की यह कला आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। फिर भी योग दिवस पर कुछ लोग विरोध कर रहे है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं परंतु प्रश्न यह है कि आखिर मन और शरीर के तमाम विकारों को दूर करने वाली विधि सांप्रदायिक कैसे हो सकती है। योग ने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि यह कला किसी धर्म को प्रेरित नहीं करती बल्कि समाज में भाई–चारा और मन को शांति भी प्रदान करती है। यह सच है कि इसकी उत्पत्ति भारतीय ऋषियों द्वारा हुई हैं परन्तु इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि इससे योग आज अछूत हो जाता है। अगर शरीर कुछ व्यायाम करने से ठीक हो सकता है वो भी आज के जमाने में, जहां प्रत्येक इलाज के लिए पैसे खर्च करने पड़ते है वही योग आपको बिना शुल्क दिए भी प्राप्त हो जाता है। अतः योग को किसी धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ❑

विकास दर में चीन से आगे निकल जाएगा भारत

विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ अध्यक्ष ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में कहा कि इस साल 7.5 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ चीन को पार कर सकता है। भारत पहली बार विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वृद्धि की संभावना के लिहाज से सबसे आगे है।

जबकि रपट के अनुसार चीन की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

हमारा शरीर पंचतव्य से बना है, ये पांचों तत्व गाय के उत्सर्जित सभी पांचों तत्वों में मिलता है। गाय का दूध, मां के दूध से भी उत्तम है, यह भी प्रमाणित हो चुका है।

- अन्नदा शंकर जी

स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय गौविज्ञान के संयुक्त तत्वाधान में पंचगव्य चिकित्सा शिविर एवं गौ कथा का आयोजन 29–30 मई को बोकारो के सेक्टर–3 सी. सरस्वती विद्या मंदिर में संपन्न हुआ। इस शिविर में कुल 197 मरीजों ने इलाज कराया, जिसमें 29 विभिन्न प्रकार के केंसर, 9 गुर्दा, 2 यकृत विकार, 2 त्वचा विकार, 70 मधुमय के मरीजों ने इस शिविर का लाभ उठाया।

इस शिविर में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख श्री अन्नदा शंकर पाणीग्रही ने कहा कि गाय एक जानवर नहीं, गाय भारतीय कृषि का मेरूदण्ड है। गाय के जानवर ही नहीं, यह मनुष्यों को जीवन देने वाली एक प्राणी है। भारतीय अर्थव्यवस्था यानि कृषि और कृषि में खेत जोतने का काम करती है, तो उसके गोबर और गोमूत्र से खाद्य एवं कीटनाशक का काम होता है। वहीं उसके दूध से बनी दही, घी, मट्ठा का उपयोग से हमारे मस्तिष्क तीक्ष्ण बुद्धि, बालक हीष्ट–पुष्ट होता है। यह हम स्वदेशी के लोग की नहीं कहते देश–विदेश के कई वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित कर दिखलाया है।

हमारा शरीर पंचतव्य से बना है, ये पांचों तत्व गाय के उत्सर्जित सभी पांचों तत्वों में मिलता है। गाय का दूध, मां के दूध से भी उत्तम है, यह भी प्रमाणित हो चुका है। अन्नदा शंकर जी ने अपने संबोधन में कहा कि देशी गाय के पीठ यानि रीढ़ की हड्डी में एक सुरकेतु नाड़ी होती है, जिस पर जैसी की सुर्य की रोशनी पड़ती है, तो उस नाड़ी से एक पीले तरल पदार्थ का रिसाव होता है, जिससे गाय में किसी भी प्रकार के जहर को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। परिणामस्वरूप गाय से उत्पन्न दुध, दही, घी का रंग पीला होता है। इसके गौमूत्र एवं गोबर में इसका अंश रहता है। गाय के गोबर से लिपे हुए घर या आंगन में परमाणु विकिरण का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे देश–विदेश के कई वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखंड प्रांत सहकार्यवाह श्री राकेश लाल जी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि पंचगव्य से औषधी का प्रयोग होता है, यह जानकारी जब मुझे प्राप्त हुई तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। यहां आने पर अपने कार्यकर्ता की मां श्रीमति सोनापरी देवी विगत 4 वर्षों से केंसर से पीड़ित थी और अपने कांचीपुरम् के वैद्य श्री निरंजन वर्मा से इलाज करा रही थी। आज वह पूर्णतयः स्वस्थ्य होने की प्रक्रिया में है। इस देखकर हम लोगों को गौ सेवा पर ध्यान देने के साथ–साथ गौ पालन में कैसे वृद्धि हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए।

समारोह में कांचीपुरम् से आए कथावाचक सह वैद्य श्री निरंजन वर्मा ने कहा कि गौ हत्या करने वालों का विरोध नहीं करना चाहिए। वह शक्ति हमें गौ के संवर्धन में लगानी चाहिए। हमें रिफाईण्ड और डबल रिफाईण्ड तेल का उपयोग नहीं कर केवल और केवल गाय का घी ही खाना चाहिए। बोकारो शहर के लोगों से अपील किया कि केवल देशी गाय का दुध मांगेंगे तो झक मारकर पशुपालक आपको देशी गाय का दूध देगा। हम लोग जर्सी को गाय मान लेते है, वस्तुतः यह सुअर और गाय का मिला हुआ जन्तु है। जिसमें देशी गाय के 2 गुण भी नहीं है। वास्तव में जर्सी का दुध पीने से गैस की समस्या तो होगी ही और आप जानते है कि कैंसर की पहली सीढ़ी भी गैस है। देशी गाय के पीठ सहलाने मात्र से रक्तचाप की बीमारी नियंत्रित हो सकती है। इसलिए समस्त महानुभावों से आग्रह है कि गाय और उसके उत्पन्न बछड़ा और बछडी का भरपूर अपने सभी कार्य में उपयोग करे, जिससे गौ संवर्धन में सहयोग मिलेगा। आपको जानकार आश्चर्य होगा कि एक गाय अपने जीवनकाल में 4 लाख 40 हजार लोगों का एक समय का भोजन व्यवस्था करती है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत बौद्धिक प्रमुख अरविन्द त्रिपाठी, विभाग कार्यवाह श्री शिवकुमार मिश्रा, बोकारो महानगर संघचालक श्री रणजीत वर्णवाल, प्रो. राजकुमार सिंह, श्री कमल सिंह, सचिन्द्र कुमार वरियार, जयशंकर प्रसाद, मुक्तेश्वर आचार्य, सुश्री रूमपा, सुश्री बसंती, श्री प्रकाश राय, श्री देवीलाल मेहतो, श्री पदम लोचन महतो, श्री दिलीप नायक सहित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ❑